



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1986/पौष 11, 1907
No. 2) NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1986/PAUSA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
एक एक संख्या

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—पार्ट 3—उप-उप (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence)

ग्रन्थ मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985

का. प्रा. 71.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के यासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में विभा विभाग को जिनके कर्मचारीयून्नत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[म. 12022/1/78—रा. प्रा. (ष-2)]
ब्रह्मपाल भला, अधिकारी सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 23rd December, 1985

S.O. 71.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Department of Education, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. 12022/1/78-OL(B-2)]
D. P. BHALLA, Under Secy.

कार्यालय और सोक विकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यालय और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985

आवेदन

का. प्रा. 72.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्पाइन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठ्ठन, धारा 5 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता की अग्रिमित हृत्या से संबंधित अपराध मामला सं. 130/85 तारीख 11 दिसम्बर, 1985, जो पुलिस थाना जी. प्रा. पी. जयपुर (राजस्थान) में रजिस्ट्रेशन किया गया, को बोबत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संघवाहक के अनुत्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे सम्बन्धित प्रयत्नों, दुष्क्रियों और घटेवारों के प्रन्त्रिपण के लिए, राजस्थान सरकार को महसूति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्पाइन के अध्ययों का शनितयों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[मंज्ञा 228/35/85--ए. को. डी. (II)]
एम. एस. प्रसाद, अधिकारी सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSION
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 26th December, 1985

ORDER

S.O. 72.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Rajasthan, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offences punishable under section 302 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences ad any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to the Crime case No. 130/85 dated 11th December, 1985 registered at Police Station GRP, Jaipur (Rajasthan) relating to the alleged murder of Shri Surendra Chandra Gupta, Advocate.

[No. 228/35/85-AVD.II]
M. S. PRASAD, Under Secy.

(पेंशन और पेंशनभोगी कास्टियन विभाग)

नई दिल्ली, 24 विसम्बर, 1985

का. आ. 73.—केन्द्रीय सरकार, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री पद्मनाभस्वामी मन्दिर अम्बाजित विवरण" को कर निर्वाचित धर्म 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली प्रबन्धि के लिए अधिसूचित करते हैं।

1. (1) इन नियमों का मंजिल साम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयृत होंगे।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के नियम 5 के उपनियम (1) में "एक वर्ष और छह मास" शब्दों के स्थान पर "30 जून, 1985 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की प्रबन्धि "शब्द रखे जाएँगे।

[र. 28/5/85—पेंशन यूनिट]

हजारा सिंह, उप सचिव

टिप्पण :—पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का का. सं. 3478 तारीख 10-9-83 के रूप में प्रकाशित किए गए और तत्परतात् का. का. सं. 789 तारीख 17-3-84 और का. का. सं. 4351 तारीख 15-12-84 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 24th December, 1985

S.O. 73.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) (Third Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, in Rule 5, in sub-rule (1), for the words 'one year and six months', the words 'a period extending upto and inclusive of the 30th day of June, 1986, shall be substituted.

[No. 26/5/85-Pension Unit]
HAZARA SINGH, Dy. Secy.

NOTE : —The payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 were published as S.O. No. 3478 dated 10-9-83 subsequently amended vide S.O. 789 dated 17-3-84 and S.O. No. 4351, dated 15-12-84.

दिल्ली मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 विसम्बर, 1985

(आयकर)

का. आ. 74.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री पद्मनाभस्वामी मन्दिर अम्बाजित विवरण" को कर निर्वाचित धर्म 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली प्रबन्धि के लिए अधिसूचित करते हैं।

[F. 6515 (का. सं. 197-ए/131/82—का. क. नि.-1]
का. के. निवारी, अवर. सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th November, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 74.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (V) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Padmanabhaswamy Temple Trust, Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6515/F. No. 197-A/131/82-JT(AI)]
R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1986

आदेश

का. आ. 75.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विवेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धरा 3 की उपधारा (1) के व्यवीत विवेष द्वप्ति से संशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/73/85-सी. शु.-VIII तारीख 20 अगस्त, 1985, यह निवारण देते हुए जारी किया था कि श्री यू. पी. श्रवृक्कर को केन्द्रीय कारागार, विवेद्वप्ति, में निवारण कर लिया जाये और अभिभावकों में रक्त जाए, ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवारित किया जा सके जो विवेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विवेशी करने का कारण है कि पूर्वोक्त अविकृष्ट फाराह हो गया है या अपने को छिपा रखा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अन. श्रवृ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवारण देती है कि पूर्वोक्त अविकृष्ट इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयकर विवेद्वप्ति के मामले हाजिर हों।

[का. सं. 673/73/85-सी. शु.-VIII]
का. के. निवारी, उप सचिव

New Delhi, the 1st January, 1986

ORDER

S.O. 75.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/73/85-Cus. VIII, dated 20th August, 1985 under the said sub-section directing that Shri V. P. Aboobacker be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/73/85-Cus. VIII]

R. K. TEWARI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985

ग्रांटेश

स्टाम्प

का. आ. 76.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो प्रांतीय वित्त निगम, चंडीगढ़ द्वारा केवल दो करोड़ तीन लाख पचास हजार रुपये मूल्य के अणपत्र (29 वां नियम) के रूप जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभाव्य है।

[रि. 45/85—स्टाम्प—फा सं. 33/60/85—वि. क.]

New Delhi, the 26th December, 1985

ORDERS

STAMPS

S.O. 76.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debenture (29th Issue) to the value of Two Crores Forty Seven Lacs and fifty thousand rupees only to be issued by the Punjab Financial Corporation, Chandigarh, are chargeable under the said Act.

[No. 45/85-Stamps-F. No. 33/60/85-ST]

का. आ. 77.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा ईंट इंडिया होटल्स लिमिटेड कलकत्ता को मात्र चार लाख पचास हजार रुपये के उत्तम नमेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी की स्वीकृति प्रदान करती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले छ. करोड़ रुपये अंकित मूल्य के “15% भारतीय विमोक्षण असम्परिवर्तनीय अग पत 1985” पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाव्य है।

[रि. 46/85—स्टाम्प—फा. सं. 33/37/85—वि. क.]

S.O. 77.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the East India Hotels Ltd., Calcutta to pay consolidated stamp

duty of Four lakhs and fifty thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on “15 per cent Secured Redeemable Non Convertible Debentures 1985” of the face value of rupees Six Crores to be issued by the said company.

[No. 46/85-Stamps-F. No. 33/37/85-ST]

का. आ. 78.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा ऑग्स्प्रेट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उड़ीसा को मात्र नो लाख, सेतोस हजार, पांच साँ सठ्ये के उस नमेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी की स्वीकृति प्रदान करती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले बारह करोड़ पचास लाख रुपये अंकित मूल्य के 3,00,000 [15% असम्परिवर्तनीय आरक्षित अणपत्र (II सिरज) तथा 9,50,000 असम्परिवर्तनीय आरक्षित अणपत्र (III) सिरज] से साँ सठ्ये वे] पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाव्य है।

[रि. 47/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/58/85-वि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

S.O. 78.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Orient Paper and Industries Limited, Orissa, to pay consolidated stamp duty of Nine lakhs thirty seven thousand five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on 3,00,000 [15 per cent Non-convertible Secured debentures (II Series) and 9,50,000 Non-convertible Secured debentures (III Series) of 100 each] of the face value of rupees Twelve Crores and fifty lacs to be issued by the said company.

[No. 47/85-Stamps-F. No. 33/58/85-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(प्राधिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1985

का. आ. 79.—बैंककारी विनियुक्त अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एततीय रिजर्व बैंक की शिकायित पर एतद्वारा घोणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपर्युक्त ग्रिडलेज बैंक पा. एल. सी., कलकत्ता पर इस अधिसूचना की तारीख से 5 नवम्बर, 1986 तक उस सीमा तक लागू नहीं होगी, जहाँ तक इनका संबंध नियन्त्रित (ज्वेंजों) के रूप में कलकत्ता स्टीम नेविगेशन कं. सि. की 30 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता से है।

[रिया एफ. 15/3/34-वि. ओ.-III]

एम. एम. मानारामन, अवर मंत्रिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 20th December, 1985

S.O. 79.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of the section 19 of the said Act shall not apply to the Grindlays Bank p.l.c. Calcutta, upto the 5th November, 1986 insofar as they relate to its holding of more than 30 per cent shares in the Calcutta Steam Navigation Co. Ltd., as pledgee.

[No. 15/3/84-B.O. III]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 विसम्बर, 1985

का. प्रा. 80—वैकारो विनियमन प्रधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवार, एक्सीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त प्रधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपर्युक्त हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, लि., हरदोई पर वो वर्ष की अवधि अर्थात् विनांक 31 विसम्बर, 1987 तक सागू मर्ही शून्ये।

[भंडा एफ. 8-2/84-ए. सी.]

New Delhi, the 23rd December, 1985

S.O. 80.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Hardoi District Co-operative Bank Ltd., Hardoi for a period of two years i.e. upto 31 December 1987.

[F. No. 8-2/84-AC]

का. प्रा. 81—वैकारो विनियमन प्रधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवार, एक्सीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त प्रधिनियम की धारा 11, उपधारा (1) के उपर्युक्त राजपत्र में इस प्रधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1986 तक बलुरघाट डेस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि. पर लागू नहीं होंगे।

[भंडा एफ. 8-1/85-ए. सी.]
के. पी. पांडियम, अब्द सचिव

S.O. 81.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of section 11 of the said Act shall not apply to the Balurghat Central Co-operative Bank Ltd., from the date of publication of this notification in the official Gazette to 30 June 1986.

[F. No. 8-1/85-AC]

K. P. PANDIAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहरणालय, मध्य प्रदेश

इंदौर, 19 नवम्बर, 1985

प्रधिसूचना संख्या 11/85

का. 10 आ. 10 8.2—श्री के. सी. लीपाणी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ममह 'ब' आवेदन भायु होने पर 31 अक्टूबर 1985 के प्रयाप्त तिथि से गरहारी सेवा से देश निवृत हो गए हैं।

[प. स. II(3) 7-गोप /85/6648]
एस. श्री. रामकृष्णन, समाहरण

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M.P.

Indore, the 19th November, 1985

NOTIFICATION NO. 11/85

S.O. 82.—Shri K. C. Tripathi, Superintendent of Central Excise, Group 'B' having attained the age of superannuation retired from Government service on the afternoon of Thirty-first October, 1985.

[C. No. II(3)7-Con/85/6648]
S. V. RAMAKRISHNAN, Collector

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पौर समाहरणालय

हैदराबाद, 16 विसम्बर, 1985

प्रधिसूचना सं. 2 /85

का. प्रा. 83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत मुख्ये प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भार-गोपालनाथन, समाहरणा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहरणालय, हैदराबाद, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173 (के), 173 (ए), 173 (एम) और 173 (एन) तथा विनांक 4-6-79 की प्रधिसूचना सं. 201/79 एवं अन्य प्रधिसूचनाओं के अनुसार, जिनमें लाईसेंस-प्रधिकारियों को शुल्क सामग्री की प्राप्ति की घोषणा प्रस्तुत करना अनेकित है, मध्यस्थि अधिकारी में उनके पास 'D-3' प्रकाशना प्रस्तुत करने में विलंब की समस्या करने की शक्ति प्रत्येकोजित करता है। यह प्रकाशना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रेज प्रधिकारियों के पास 4 दिनों तथा संबद्ध लेन्ड-धिकार के सहायक समाहरणालयों के पास 7 दिनों की अवधि तक दी जा सकती है।

[फाइल स. IV/16/89/85 ए. पी.]

आर. गोपालनाथन, समाहरण

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Hyderabad, the 16th December, 1985

NOTIFICATION No. 2/85

S.O. 83.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, R. Gopalnathan, Collector of Central Excise, Hyderabad, hereby delegate the powers of the Collector for condonation of delay in presentation of "D-3" intimation required to be filed with the proper officer in terms of Rules, 173K, 173L, 173M and 173N of the Central Excise Rules, 1944 and Notification No. 201/79 dated 4-6-79 and similar other Notifications requiring the licensees to file declaration of receipt of excisable goods, upto a period of 4 days to the Range Superintendents and upto a period of 7 days to the jurisdictional Assistant Collectors of Central Excise.

[C. No. IV/16/89/85-MP]
R. GOPALNATHAN, Collector

वाणिज्य बंजारालय

(मूल्य नियंत्रक, भ्रायात एवं निर्वात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 23 विसम्बर, 1985

आदेश

का. प्रा. 84—श्री प्रियावली मुख्यरेसन कैलांगम, पी. ओ. वाल्स 3532, आबू बाबी को एक नग किल्ट 131/1600 सी. सी. कार का आवात करने के लिए 42,500 रुपये मात्र मूल्य का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी./जे/3052185, दिनांक 2-8-85 दिया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुसिद्धि प्रति जारी किए जाने के लिए इस आवात पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थि हो गया है / खो गया है। आगे यह कहा गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्रधिकारी के पास पंजीकृत नहीं थी तथा इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी परमिट का मूल्य विकल्प भी उपयोग में नहीं आया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक न उचित व्यायिक प्रधिकारी के समक्ष विविवत, अपने लेफ्ट एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। मैं, तदनुसार संतुष्ट हूँ कि मूल संभा शुल्क निकासी परमिट सं. पी./जे/3052185, दिनांक 2-8-85 आवेदक द्वारा खो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित, भ्रायात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-85

की उपधारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदर्शन भविकारों का प्रयोग करते हुए, श्री पिनवासल सुन्दरेश्वर कैलाइशम की जारी किया गया उक्त भूमि सोमार गुला निकासी परमिट सं. पी/जे/3052185, विनाक 2-8-85 एतद्वारा द्वारा किया जाता है।

3. पार्टी को साथा शुल्क निकासी परमिट को एक अनुसिपिक प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल नं. प. /क-47 / 85-86 / गी.एल.एस/2617]
एन. एस. शुणामूर्ति, उप भूमि विवरक, अधिकारी एवं निर्यात
कर्ते द्वारा विवरक, वायाप एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 23rd December, 1985

ORDER

S.O. 84.—Mr. Pinnavasal Sundaresan Kailasam, P.O. Box 3532, Abu-Dhabi was granted Customs Clearance Permit No. P/J/3052185 dt. 2-8-85 for Rs. 42,500 only for import of One No. Fiat 131|1600 cc car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3052185 dt. 2-8-85 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred Under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3052185 dt. 2-8-85 issued to Mr. Pinnavasal Sundaresan Kailasam is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/K-47/85-86/BLS/2617]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of
Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1985

का० प्रा० 85—यत्। पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का, आ. स. 3483 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम्मीदवालों से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् : सभीम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और ग्रामे, यत् : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के असात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विविलय किया है।

अब, यत् : उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अर्जित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वीचित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोग के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और ग्रामे उस बाध की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बाध तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त स्पष्ट में, ओपण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

मनुसूची 1

कूप नं. I-10 से कूप नं. 50

राज्य : गुजरात जिला : भसव तालुका : हासोटा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	मा.।	से.
दीगस	227	0	21	06
	241	0	11	96
	244	0	22	10
	245	0	12	74
	208	0	03	90
	206	0	08	84
	200	0	13	65

[म. अ० 12016/87/85-ओ. एनजी. डी. 4]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 19th December, 1985

S.O. 85.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3483 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL NO. I-10 TO WELL NO. 50
State : Gujarat District : Bharuch Taluka Hansot

Village	Block No.	Hectare	Acre Centiare
DIGAS	227	0	21 06
	241	0	11 96
	244	0	12 10
	245	0	82 74
	208	0	03 90
	206	0	08 84
	200	0	13 65

[No O-12016/87/85-ONG-D-4]

का, आ. 86—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रबंधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रविसूचना का, आ. सं. 2905 तारीख 10-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रविसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अनिवार्य करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सदाम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रविसूचना से मंत्रगत अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में हैं उपयोग का अधिकार अनिवार्य करने का विनियम किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी आधारों से मुक्त रूप में, विषयाण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ऐस. एन. ए ऐस. एस. सी. टी. एफ. हाईटर

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना

गाँव	संख्या.	हे.	आर.	सं.
संयाल	598	0	09	00
	597	0	13	50
	577	0	03	70

[सं. ओ-12016/72/85-ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 86.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2905 dated 10-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from S.N.A.A. to S.S. CTF Header

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	598	0	09	00
	597	0	13	50
	577	0	03	70

[No O-12016/72/85-ONG-D 4]

का, आ. 87—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रबंधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रविसूचना का, आ. सं. 2913 तारीख 14-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रविसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अनिवार्य करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रविसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अनिवार्य करने का विनियम किया है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रविसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अनिवार्य करने का विनियम किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस प्रविसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनिवार्य किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी आधारों से मुक्त रूप में, विषयाण के प्रकाशन की इस तारीख निहित होगा।

अनुसूची

ऐस. बी. डी. आर. से सी. टी. एफ. सोमानण

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मैहसाना

गाँव	ब्लॉक	हे.	आर.	सं.
हेवुआ	250	0	52	80
	263	0	03	48
	280	0	37	08
	कार्ट ट्रैक	0	01	80
	54	0	07	80
	55	0	03	96
	56	0	01	68
	71	0	08	16
	70	0	07	50
	69	0	00	72
	67	0	03	84
	289	0	08	28
	65	0	06	96

[सं. ओ-12016/77/85 ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 87.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2913 dated 14-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

; Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

; And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From SBDR To CTF. SOB.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	250	0	52	80
	263	0	03	48
	280	0	37	08
	Cart track	0	01	80
	54	0	07	80
	55	0	03	96
	56	0	01	68
	71	0	08	16
	70	0	07	50
	69	0	00	72
	67	0	03	84
	289	0	08	28
	65	0	06	96

[No. O-12016/77/85-ONG-D 4]

का. आ. 88—यह पेट्रोलियम और जूनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और जूनिज सरकार द्वारा उपयोग के प्रधिकार का अधिसूचना का, आ. सं. 3482 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के प्रधिकार को पाइपलाइनों को विभाने के लिए अंजित करने का अपना आण्य घोषित कर दिया था।

और यह: सरम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचारकरने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का प्रधिकार अंजित करने का विनिश्चय किया है।

अब अंत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मंजित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का प्रधिकार पाइपलाइन विभाने के प्रयोग के लिए एतद्वारा अंजित किया जाता है।

और आगे उम धारा की उपधारा (4) द्वारा मंजितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेव और प्राकृतिक गैस उपयोग में, सभी बाधाओं से सुकृत रूप में, खंडण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पैन. के. ए. डब्लू. से एन. के. जी. एम-II

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरामगम

गाँव	सर्वे नं.	हे.	आर.	से.
बालसासन	413	0	01	00
	402/3	0	06	84
	402/2	0	02	75
	403	0	10	80
	402/1	0	07	20
	398	0	06	50

[सं. अ-12016/86/85-ओ एम-जी-4]

S.O. 88.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3482 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

; And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

; And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

; And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From NKAW To NK.GGS II

State : Gujarat: District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balsasan	413	0	01	00
	402/3	0	06	84
	402/2	0	02	75
	403	0	10	80
	402/1	0	07	20
	398	0	06	50

[No. O-12016/86/85-ONG-D 4]

का. आ. 89—यह पेट्रोलियम और जूनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)

की धारा 3 के उपधारा (1) के प्रवीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का, आ. सं. 2137 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अन्तिम कारण का प्रत्यान आशय घोषित कर दिया था।

और यह: सकम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रवीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अन्तिम कारण का विनिष्चय किया है।

अब, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अन्तिम किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेव और प्राकृतिक रूप से भावोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. ई. टी. से रेलवे कासिंग

राज्य: गुजरात विलास: प्राइवेट लाइन तालुका: विरसगाम

गाँव	क्षेत्र नं.	हे.	भार.	से.
सुजपुरा	85/7	0	11	64
	86/4	0	07	44
	86/1	0	17	00

[सं. O-12016/48/85-ओ. एन. जी.-जी 4]

पी. के. राजगोपालन, ईस्क अधिकारी

S.O. 89.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2137 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NKET to Railway Crossing

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
Sujpura	85/7	0	11	64
	86/4	0	07	44
	86/1	0	17	00

[No. O-12016/48/85-ONG-D 4]

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई विम्ली, 30 दिसम्बर, 1985

का. आ. 80:—यह: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रवीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का, आ. सं. 3475 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अन्तिम किया जाता था।

और आगे यह: सकम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रवीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अन्तिम करते का विनिष्चय किया है।

अब, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अन्तिम किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रूप प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेमी जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाठा संख्या	लिया गया	विवरण ग्रंथालय
1	2	3	4	5	6	7
इटापा	ओरणा	ओरणा	मोलेम	298	0	01
			पुर	299	0	57
			नवम-	310	0	02
			सिंह	1	0	32
				2	0	44
				3	0	02
				14	0	21
				19	0	08

[सं. O-14016/72/84-जी. पी.]

New Delhi, the 30th December, 1985

S.O. 90.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3475 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B. J. GAS Pipeline Project

Distr : Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark	
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Solampur	298	0	01	
		Nawal	299	0	05	
		Singh	310	0	02	
			1	0	32	
			2	0	44	
			3	0	02	
			14	0	21	
			19	0	08	

[No. O-14016/72/84-GP]

का. आ. 91.—यह: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक जित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में जंक्शन पाइट (पी. 221) एन. टी. पी. सी. से अन्ता (राजस्थान) तक ऐट्रीलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राप्तिकरण लिमिटेड, ब्राह्मण विलाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विलास के प्रयोजन के लिए एतत्पावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब ऐट्रीलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रबंधन) प्रधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त एकित्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतत्पावद घोषित किया है।

बाशते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइपलाइन विलास के लिए आवेदन समझ प्राप्तिकारी, भारतीय गैस प्राप्तिकरण लिमिटेड, एच. बी. जे. और पाइपलाइन परियोजना, 49 इकड़ा कालोटी, सदार्ह मालोतुर की इस अधिकृतवाली की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

1312 GU/85—2.

और ऐसा आवेदन करने वाला हर व्यक्ति विविष्टतया यह भी कथन करेगा कि यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

जंक्शन पाइट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी. अन्ता (राज.) तक पाइपलाइन विलास के लिए

राज्य: राजस्थान, जिला: कोटा, तहसील: मांगरोल, मुक्त तहसील: अन्ता

गाँव	खसरान.	हेक्टर	आर	सेमीआर
1	2	3	4	5
सोरखण्ड कला	1098	0	55	55
	1120	0	23	81
	1121	0	28	27
	1122	0	67	48
	1378	0	10	22
	1380	0	06	18
	1381	0	15	92
	1382	0	43	23
	1387	0	19	01
	1401	0	06	18

[सं. O-14016/524/85-गी. पी.]

S.O. 91.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Junction Point (P-221) NTPC location at Anta in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Project, 58, Bal Mundir Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Junction Point (P-221) to NTPC Location at Anta (Raj.)

State : Rajasthan, District : Kota,	Tehsil : Maangrol			
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sorkhand Kalan	1098	0	55	55
	1120	0	23	81
	1121	0	28	27
	1122	0	67	48
	1378	0	10	22
	1380	0	06	18
	1381	0	15	92
	1382	0	43	23
	1387	0	19	01
	1401	0	06	18

[No. O-14016/524/85-GP]

पा. आ. 92.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में जंकशन पाईट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी. अन्ता (राजस्थान) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एसटुपाइप अनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

प्रतः भव पेट्रोलियम और स्टेनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का प्रधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्तें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आलेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, एन. टी. पी. सी. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49 इन्ड्रा कालोनी गवाई माधोपुर की इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आलेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह आहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

जंकशन पाईट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी., अन्ता (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा, तहसील मांगरोल : सब तहसील : अन्ता

पांच	संस्कारन	हेक्टर	भार	सेक्टीन्यार
1	2	3	4	5
तामस्केडा	301	0	12	00
	225	0	20	79
	226	0	30	36
	224	0	08	91
	222	0	31	79
	223	0	18	16
	218	0	02	01
	216	0	75	24
	217	0	00	20
	208	0	57	98
	211	0	51	78
	213	0	24	60
	212	0	09	03
	196	0	49	31
	197	0	34	69
	198	0	29	34
	161	0	29	94

[स. O-14016/526/85-गी. पी.]

S.O. 92.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Junction Point (P-221) to NTPC location at Anta in Rajasthan State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land), Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Project, 58, Bal Mandir Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Junction Point to (P-221) NTPC Location at Anta (Raj)

STATE : Rajasthan, District : Kota, Tehsil : Maangrol, Sub Tehsil Anta

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
Tamkheda	301	0	12	00
	225	0	20	79
	226	0	30	36
	224	0	08	91
	222	0	31	79
	223	0	18	16
	218	0	02	01
	216	0	75	24
	217	0	00	20
	208	0	57	98
	211	0	51	78
	213	0	24	60
	212	0	09	03
	196	0	49	31
	197	0	34	69
	198	0	29	34
	161	0	29	94

[No. O-14016/526/85-GP]

का० आ. 93.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में जंकशन पाईट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी. अन्ता (राजस्थान) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एसटुपाइप अनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

प्रतः भव पेट्रोलियम और स्टेनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का प्रधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्तें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आलेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, एन. टी. पी. सी. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49 इन्ड्रा कालोनी, सबाई माधोपुर की इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा ग्राहक परने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह बाहुदा है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जंक्शन पाईट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी. अन्ता (राज.) तक पाइपलाइन विद्युत के लिए
राज्य : राजस्थान, ज़िला : कोटा, तहसील : मांगरोल, सब तहसील : अन्ता

पांच	खसरा नं.	हैक्टर	आर	सेन्टी- आर
1	2	3	4	5
काचरी	267	0	02	85
	266	0	12	12
	268	0	04	75
	269	0	53	46
	270	0	01	81
	271	0	23	62
	272	0	56	51
	284	0	00	03
	283	0	20	20
	282	0	26	96
	281	0	32	08
	278	0	03	21
	352	0	31	65
	351	0	02	56
	346	0	84	15
	361	0	35	59
	362	0	13	55
	363	0	70	80
	369	0	29	95
	370	0	04	51

[सं. O-14016/525/85-जी. पी.]
एम. एस. श्रीनिवासन, विवेशक

S.O. 93.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Junction Point (P-221) to NTPC location at Anta in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Project, 58, Bal Mandir Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Junction Point (P-221) to NTPC location at
Anta (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Anta.

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
Kachari	267	0	02	85
	266	0	12	12
	268	0	04	75
	269	0	53	46
	270	0	01	81
	271	0	23	62
	272	0	56	51
	284	0	00	03
	283	0	20	20
	282	0	26	96
	281	0	32	08
	278	0	03	21
	352	0	31	65
	351	0	02	56
	346	0	84	15
	361	0	35	59
	362	0	13	55
	363	0	70	80
	369	0	29	95
	370	0	04	51

[No. O-14016/525/85-GP]

M.S.SRINIVASAN, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985

का. आ. 94.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (शर्जन और विकास) प्रधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की प्रधिसूचना सं. का. आ. 3356 द्वारा उस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का शर्जन करने के आने वाली की सूचना थी;

श्रीर सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त प्रधिनियम की धारा 8 के अनुसार में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्योक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 900.00 एकड़ (लगभग) या 364.21 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का शर्जन किया जाना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 900.00 एकड़ (लगभग) या 364.21 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का शर्जन किया जाता है।

2. इस प्रधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला विभाग, 1-काउंसिल हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुसूची) दरबंदा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

भनुसूची

पिपरवार विस्तार ब्लाक

उत्तरी करणपुर कोयला क्षेत्र

झाँग सं राजस्व/19/85-तारीख 27-3-85

(जिसमें अंजित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्र सं	ग्राम	पाना	पाना संख्यांक	जिला	धोन्त	टिप्पणी
1. किछटो		ठडवा	78/235	हजारीबाग	358.94	भाग
2. पिपरवार या मंगरडाहा		"	80/237	"	86.35	भाग
3. बिजैन		"	83/240	"	222.86	भाग
4. सिदालू		"	84/241	"	64.00	भाग
5. बेस्ती		"	97/254	"	167.85	भाग

कुल धोन्त—900.00 एकड़ (लगभग)

या—364.21 हैफ्टर (लगभग)

ग्राम किछटो में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 (भाग), 2 (भाग), 5 (भाग), 6, 7, 8 (भाग), 31 (भाग), 32, 33, 34 (भाग), 56 (भाग), 59 (भाग), 60 (भाग), 61 से 72, 73 (भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 134 (भाग), 137 (भाग), 138 (भाग), 139 (भाग), 140, 141 (भाग), 142 (भाग), 144 (भाग), 145 (भाग), 146, 147, 148 (भाग), 149, 151 (भाग) 152 (भाग), 153 (भाग), 154 से 165, 166 (भाग), 167, 168, 169, 170 (भाग), 171 (भाग), 175 (भाग), 176, 177 (भाग), 203 (भाग), 222 (भाग), 223, 224, 225 (भाग), 227 (भाग), 228 से 241, 242 (भाग), 243 (भाग), 244 (भाग), 246 से 282, 283 (भाग), 284 से 290, 291 (भाग), 292 (भाग), 294 (भाग), 295 से 305, 306 (भाग), 320 (भाग), 321 से 324, 325 (भाग), 329 (भाग), 330 से 353, 354 (भाग), 356 (भाग), 357, 361 (भाग), 392 (भाग), 534 (भाग), 536 (भाग), 537 (भाग), 558 (भाग), 559 (भाग), 633 (भाग), 643 (भाग), 648 (भाग), 653 (भाग), 654 से 660, 662 (भाग) और 663 (भाग).

ग्राम पिपरवार या मंगरडाहा में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक :—

1, 2 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग), 16 से 21, और 22 (भाग),

ग्राम बिजैन में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक :—

265 (भाग), 266 से 277, 278 (भाग), 279 (भाग), 280 से 294, 338, 340 और 341.

ग्राम सिदालू में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक :—

4 (भाग), 127 (भाग), 142 (भाग), 144 (भाग), 157 (भाग), 158 (भाग), 160 (भाग), 161, 162, 163 (भाग), 164 (भाग), 165 (भाग), 169 (भाग), 170, 171 (भाग), 172, 173, 174 (भाग), 175 (भाग), 176, 177, 178 (भाग), 179 से 183, 184 (भाग), 185 (भाग) 187 और 188 (भाग).

ग्राम बेस्ती में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक

1 से 8, 9 (भाग), 10 से 18, 19 (भाग), 20 (भाग), 21 (भाग), 28 से 32, 33 (भाग), 34 (भाग), 35, 36 (भाग), 45 (भाग), 52 (भाग), 72 (भाग), और 647 (भाग).

सीमा वर्णन :

क.—ख.—ग रेखा सिदालू ग्राम में सारेखा गाला में प्लाट संख्यांक 4, 188, 163, 160, 158, 157, 174, 175,

ग—घ—ड

144, 142, 185, 127 और 185 तथा प्लाट संख्यांक 119 की भागत: पूर्वी सीमा में गुजरती है और तब बिजैन ग्राम में प्लाट संख्यांक 265 से गुजरती है, तत्प्रवात, नाले की मध्य रेखा के उस भाग के साथ साथ जाती है जो बिजैन और बेस्ती तभा कुटकी खुदे व बेस्ती ग्रामों की सम्मिलित सीमा है तथा चिन्ह "ग" पर मिलती है।

रेखा बेस्ती ग्राम में प्लाट संख्यांक 72, 19, 20, 21, 19, 45, 33, 34, 36, 19, 52, 9 और 647 से होकर जाती है, और फिर ग्राम बिजैन में प्लाट संख्यांक 279 और 278 से होकर जाती है और तब ग्राम पिपरवार या मंगरडाहा में प्लाट संख्यांक 2, 15, 14, और 22 में से गुजरती है, ग्राम किछटो (जो कोयला अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अंजित पिपरवार ब्लाक की सम्मिलित सीमा है) में प्लाट संख्यांक 1, 8, 31, 170, 171, 166, 175, 177, 244, 243, 242, 203, 222, 225, 227, 306, 329, 325, 320, 559, 558, 537, 633, 643, 648, 653, 662 और 663 में से होकर जाती है तथा चिन्ह "ह" पर मिलती है।

रेखा शामोदार नदी की मध्य रेखा के उस भाग के साथ साथ जाती है जो कोरीगारा और किंबों ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और चिन्ह "क" पर मिलती है।

रेखा, ग्राम किछटो में प्लाट संख्यांक 534, 536, 537, 558, 392, 354, 356, 361, 392, 294, 291, 292, 283, 134, 238, 137, 138, 137, 139, 141, 142, 145, 144, 148, 153, 152, 151, 73, 74, 75, 59, 60, 56, 31, 34, 5 और 2 में से होकर जाती है और चिन्ह "छ" पर मिलती है।

रेखा, नाला की मध्य रेखा के उस भाग के साथ-साथ जाती है जो पिपरवार या मंगरडाहा और कलोदा, बिजैन और कलोदा ग्रामों की सम्मिलित सीमा है तथा बिजैन और राजधार ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भी साथ साथ जाती है और चिन्ह "ज" पर मिलती है।

रेखा, सिदालू ग्राम में प्लाट संख्यांक 185, 184, 178, 185, 171, 169, 163, 164, 165 और

ज—क

4 से होकर जाती है श्रीर प्रारंभिक विमु "क" पर
मिलती है।

[म. 43015/18/85-सी. ए]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 23rd December, 1985

S.O. 94.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3356 dated the 27th October, 1984, under Sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 900.00 acres (approximately) or 364.21 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto; should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 900.00 acres (approximately) or 364.21 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

(Piparwar Extension—Block
(North Karanpura Coalfield)

Drg. No. 19/85

Dated 27-3-1985

(Showing lands acquired)

All Rights

Serial Number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1. Kichto		Tandwa	78/235	Hazaribagh	358.94	Part
2. Piparwar or Mangardaha		..	80/237	..	86.35	Part
3. Bijain		..	83/240	..	222.86	Part
4. Sidalu		..	84/241	..	64.00	Part
5. Bentti		..	97/254	..	167.85	Part
Total area: 900.00 acres (approximately) or 364.21 hectares (approximately)						

Plot number acquired in village Kichto

1(Part), 2(Part), 5(Part), 6, 7, 8(Part), 31 (Part), 32, 33, 34(Part)
56(Part), 59(Part), 60(Part), 61 to 72, 73(Part), 74(Part),
75(Part), 134(Part), 137(Part), 138(Part), 139(Part), 140, 141,
(Part), 142(Part), 144(Part), 145(Part), 146, 147, 148(Part), 149
(151(Part), 152(Part), 153(Part), 154 to 165, 166(Part), 167,
168, 169, 170(Part), 171(Part), 175(Part), 176, 177(Part),
203(Part), 222(Part), 223, 224, 225(Part), 227(Part), 228 to
241, 242(Part), 243(Part), 244(Part), 246 to 282, 283(Part),
284 to 290, 291(Part), 292(Part), 294(Part), 295 to 305, 306
(Part), 320(Part), 321 to 324, 325 (Part), 329 (Part), 330 to
353, 354 (Part), 356 (Part), 357, 361 (Part), 392 (Part), 534
(Part), 536(Part), 537 (Part), 558 (Part), 559 (Part), 633 (Part),
643 (Part), 648 (Part), 653 (Part), 654 to 660, 662 (Part), and
663 (Part).

Plot numbers acquired in village Piparwar or Mangardaha:

1, 2 (Part), 14 (Part), 15 (Part), 16 to 21, and 22 (Part).

Plot numbers acquired in village Bijain :

265 (Part), 266 to 277, 278 (Part), 279 (Part), 280 to 294
338, 340 and 341.

Plot numbers acquired in village Sidalu :

4 (Part), 127 (Part), 142 (Part), 144 (Part), 157 (Part), 158
(Part), 160 (Part), 161, 162, 163 (Part), 164 (Part), 165 (Part),
169 (Part), 170, 171 (Part), 172, 173, 174 (Part), 175 (Part),
176, 177, 178 (Part), 179 to 183, 184 (Part), 185 (Part), 187
and 188 (Part).

Plot numbers acquired in village Bentti

1 to 8, 9 (Part), 10 to 18, 19 (Part), 26 (Part), 21 (Part), 29
to 32, 33 (Part), 34 (Part), 35, 36 (Part), 45 (Part), 52 (Part),
72 (Part), and 647 (Part)

Boundary Description :

A-B-C Lines pass through plot numbers 4, 188, 163,
160, 158, 157, 174, 175, 144, 142, 185, 127 and
185 and part eastern boundary of plot number
119 in Sarewa Nalla In village Sidalu then
through plot number 265 in village Bijain,

then passes along part Central line of the Nalla which forms common boundary of villages Bijain and Bent and Kutkhurd and Bent and meets at point 'C'.

C-D-E lines pass through plot numbers 72, 19, 20, 21, 19, 45, 33, 34, 36, 19, 52, 9 and 647 in village Bent through plot numbers 279, and 278 in village Bijain, through t numbers 2, 105e 14 and 22 in village Piparwar or Mangardaha, through plot numbers 1, 8, 31, 170, 171, 166, 175, 177, 244, 243, 242, 203, 222, 225, 227, 306, 329, 325, 320, 559, 558, 537, 633, 643, 648, 653, 662 and 663 in village Kichto (which forms part common boundary of Piparwar block acquired U/s 9 (1) of the Coal Act) and meets at point 'E'.

E-F line passes along part Central line of Damodar River which forms common boundary of village Korigara and Kichto and meets at point 'F'.

F-G line passes through plot numbers 534, 536, 537, 558, 392, 354, 336, 392, 361, 294, 291, 292, 283, 134, 238, 137, 138, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 144, 148, 153, 152, 151, 73, 74, 75, 59, 60, 56, 31, 34, 5 and 2 in village Kichto and meets at point 'G'.

G-H line passes along part Central line of the Nalla (which forms common boundary of villages Piparwar or Mangardaha and Bahera, Piparwar or Mangardaha and Kanauda, Bijain and Kanauda and also along common boundary of villages Bijain and Rajdhar and meets at point 'H'.

H-A line passes through plot numbers 185, 184, 178, 185, 171, 169, 163, 164, 165 and 4 in village Sidalu and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/18/85-CA]

गर्द विलो, 26 दिसंबर, 1985

का. आ. 95.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपर्युक्त भूमि में उल्लिखित भूमि में कोयला प्रधिप्राप्त किए जाने की संभावना है।

ग्रन्त, केन्द्रीय सरकार, कोयला बारक झेल (प्रजन और विकास) प्रधिनियम, 1967 (1967 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धेल में कोयले का पूर्वेषण करते के अपने ग्राम्य की सुधारा देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले धेल के रेखांक सं. बी. सी. सी. एस./दि. डी./50-85 और की. सी. सी. एस./दि. 51-85 तारीख 31-8-1985 का निरीक्षण कलाक्षट, धनबाद (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्तिसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या नियंत्रक (नियमित योजना और परियोजना) भारत कोकिंग कोल लि., कोयला धवन, ढाकघर कोयला नगर, जिला धनबाद (बिहार) में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितवद सभी घटित उक्त प्रयोगिताम की धारा 13 की उपधारा (7) में निविष्ट सभी नवायों, चार्ट्स और अन्य वस्त्रावेगों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख

से नव्वे विन के भीतर, नियंत्रक (संक्षिया) परिवर्तन, भारत कोकिंग कोल लि. धनबाद (बिहार) को भेजेगा।

प्रत्यक्षी

सिंगरा ब्लॉक "ग"

सरिया कोयला धेल

(झोलुंग सं. बी. सी. सी. एस./दि. डी./50 (पूर्वेषण के लिए अधिसूचित और 51-8-5 तारीख 31-8-1985
भूमि)

क्र.सं.	ग्राम	थानासं.	धाना	जि. धेल (एकड़ी में)	टिप्प- णिया
1.	मोनीझीह	85	सरिया	धनबाद	10,240 भाग
2.	गरमूडीह	86	"	"	14,750 "
3.	सरायडाहा	87	"	"	83,260 संगूण
4.	लकड़बारी	88	"	"	114,920 "
5.	कारीतानर	89	"	"	45,800 भाग
6.	तेतंगबाद	90	"	"	90,520 संगूण
7.	मालीला डीह	91	"	"	90,250 भाग
8.	बरझूभी	92	"	"	68,640 "
9.	बालूझीह	93	"	"	0.602 "
10.	बुवराजपुर	94	"	"	16,000 "

534.972 ईक्टर (भगवग)

या 321.28 एक्ट (सगवग)

सिंगरा ब्लॉक "ग" का सीमा तर्फ

सरिया कोयला धेल

क-ख	रेखा, मौजा मरमूडीह, मोनीझीह और बुवराजपुर के धेलों में से होकर जाती है।
ग-ग	रेखा, मौजा बुवराजपुर और बरझूभी के धेलों में से होकर जाती है।
ग-ग/1	रेखा, मौजा बरझूभी के धेलों में से होकर जाती है।
ग/1-2	रेखा, मौजा बरझूभी के धेलों में से होकर जाती है।
डी/1-३	रेखा, मौजा कारीतानर के धेलों में से होकर जाती है।
डृ-१	रेखा, मौजा मालीला डीह के धेलों में से होकर जाती है।
च-छ	रेखा, मौजा मालीला डीह के धेलों में से होकर जाती है।
छ-ज-	रेखा, मौजा तेतंगबाद की दोमोदर नदी के परिवर्ती तट के साथ-साथ जाती है।
ज-झ	रेखा, मौजा तेतंगबाद की दोमोदर नदी के उत्तरी तट के साथ-साथ जाती है।
झ-	रेखा, मौजा तेतंगबाद, मालीला डीह, कारीतानर और लकड़बारी की कातरी नदी के पूर्वी तट के साथ-साथ जाती है।
झ-ट	रेखा, मौजा लकड़बारी और सरायडाहा की कातरी नदी के उत्तरी तट के साथ-साथ जाती है।
ट-क-	रेखा, मौजा सरायडाहा और मरमूडीह की कातरी नदी के पूर्वी तट के साथ-साथ जाती है।

[स. 43016/25/85-सी. ए. [
ममय निह, अधिकारी तत्त्वज्ञ

New Delhi, the 26th December, 1985

S.O. 95—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The Plan No. BCCL/ED/50-85 and BCCL/ED/51-85 dated 31-8-85 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Dhanbad (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in office of the Director (Corporate Planning and Project) Bharat Coking Coal Limited, Koyala Bhavan, Post Office Koyla Nagar, District Dhanbad (BIHAR). All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Director (Operation) West, Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad (Bihar) within ninety days from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

SCHEDULE

Drawing No. BCCL/ED/50 and 51-85 Dated 31-8-85		Singra Block "C" Jharia coal-field		(Showing land notified for prospecting)		
S.No.	Village	Thana No.	Thana	District	Area in Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Maṇidih	85	Jharia	Dhanbad	10.240	Part
2.	Garbhudih	86	"	"	14.750	"
3.	Saraidoha	87	"	"	83.250	Full
4.	Lakarkhawari	88	"	"	114.920	"
5.	Karitanr	89	"	"	45.800	Part
6.	Tetangabad	90	"	"	90.520	Full
7.	Majhiladīh	91	"	"	90.250	Part
8.	Bardubhi	92	"	"	68.640	"
9.	Baludih	93	"	"	0.602	"
10.	Dubrajpur	94	"	"	16.000	"

534.972 Hectares
(Approximately) or
1321.28 Acres (Approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION OF
SINGRA BLOCK "C"
JHARIA COALFIELD

A—B Line passes through the plots of Mouzas Garbhudih, Monidih and Dubrajpur.

B—C Line passes through the plot of Mouza Dubrajpur and Bardubhi.

C—C/1 Line passes through the plots of mouza Bardubhi.

C/1—D —do— of Mouza Bardubhi.

D—E —do— of Mouza Karitanr

E—F —do— of Mouza Majhiladīh

F—H —do— of Mouza Majhiladīh

G—H Line passes along the Western Bed of River Damodar of Mouza Tetangabad

H—I Line passes along the Northern Bed of River Damodar of Mouza Tetangabad

I—J Line passes along the Eastern bed of River Katri of Mouza Tetangaba, Majhiladīh, Karitanr and Lakarkhawari

J—K Line passes along the Northern bed of River Katri of Mouza Lakarkhawari and Saraidaha.

K—A Line passes along the eastern bed of River Katri of Mouzas Saraidaha and Garbhudih.

(विषय विभाग)

मई विल्ली, 26 दिसंबर, 1985

का. आ. 96:—मरकारी स्थान (अधिकृत अधिकारियों की बेवजही) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तात्परिका के कालम (1) में उल्लिखित राष्ट्रीय ताप-विषय नियम लिंग (एक नियमित निकाय) के अधिकारी जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष है, को कठिन अधिनियम के प्रशीजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो ऊपर उल्लिखित तात्परिका के कालम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मरकारी स्थानों के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का, आपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उपयोग कर सकेगा तथा उसे संपै गये कर्तव्यों का पालन करेगा।

तात्परिका

अधिकारी का पद-नाम	मरकारी स्थानों की श्रेणियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ
(1)	(2)
अधिकारी का पद-नाम रिहन्द	मरकारी स्थानों की श्रेणियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ रिहन्द स्पेशल नियम लिंग, पौ. रिहन्द नगर, जिला-मिर्जापुर, (उत्तर प्रदेश) के स्वामित्व वाली, पट्टे पर सी गई अथवा किशये पर नी गई भूमि, फ्लाटर, सम्पदा, सम्पत्ति और अन्य आवास।

[मं. 7/15/85-प०एस० (सी०टी०)]
के०एस० विष्वास, अध्यक्ष सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 26th December, 1985.

S.O. 96:—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Un-authorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer of the National Thermal Power Corporation Limited, a Corporate authority, equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India, to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Chief Personnel Manager, All lands, quarters, estate, properties and other accommodation owned, leased or rented by Rihand Super Thermal power Corporation Limited P.O. Rihand Nagar, District Mirzapur, Uttar Pradesh.	Rihand.

[No. 7/15/85-US (CT)]
K.N. BISWAS, Under Secy

स्वास्थ्य और दैरिवार कल्याण मंत्रालय

मई विल्ली, 19 दिसंबर, 1985

का. आ. 97:—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के बावजूद अधिनियम की तुसीती अनुसूची में एतद्वारा आगे और निम्नलिखित मंजूरीन करनी है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में “उत्तर प्रदेश” शीर्ष के प्रमत्तीत क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जायें, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय	मान्यता प्राप्त विकित्सा प्रहृता संस्था का नाम	पंजीकरण के लिये संकेतात्मक	टिप्पणियाँ
“15 क. आग्रा”	मैचलर आफ आग्रा।	बी०एस० एम० बी०एस० एम० 1982 से बाय	
विश्वविद्यालय	मैडिकल पाइ		
	वैचलर आफ।	सर्जरी	

[सं. वी० 27021/6/82-होम्यो।
पी०एस० कपूर, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th December, 1985

S.O. 97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading ‘Uttar Pradesh’ after serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

Name of University Board or Medical Institution	Recognised medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
1	2	3	4
“15 A. Agra University, Agra.	Bachelor of Medicine and Surgery	B.M.S.	From 1982 onwards.”

[No. V. 27021/6/82-Homoeo]

P.L. KAPUR, Desk Officer (Homoeo)

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1985

(पुरातत्त्व)

का. आ. 98 :—केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और प्रबलेप अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित के अनुसार, भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की एक अधिसूचना से का.आ. 2075 तारीख 27 अगस्त, 1985 द्वारा, जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 मई, 1985 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिरिप्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते के प्रपते आशय की सूचना दी थी और उस अधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक के समीप एक सहजपूर्ण स्थान पर सगा थी वही थी:

और उक्त राजपत्र जनता को 13 मई, 1985 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार को जनता के कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुआ है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त विविधों का प्रयोग करते हुए इससे उपादान अनुसूची में विनिरिप्ट आशीर्वाद संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

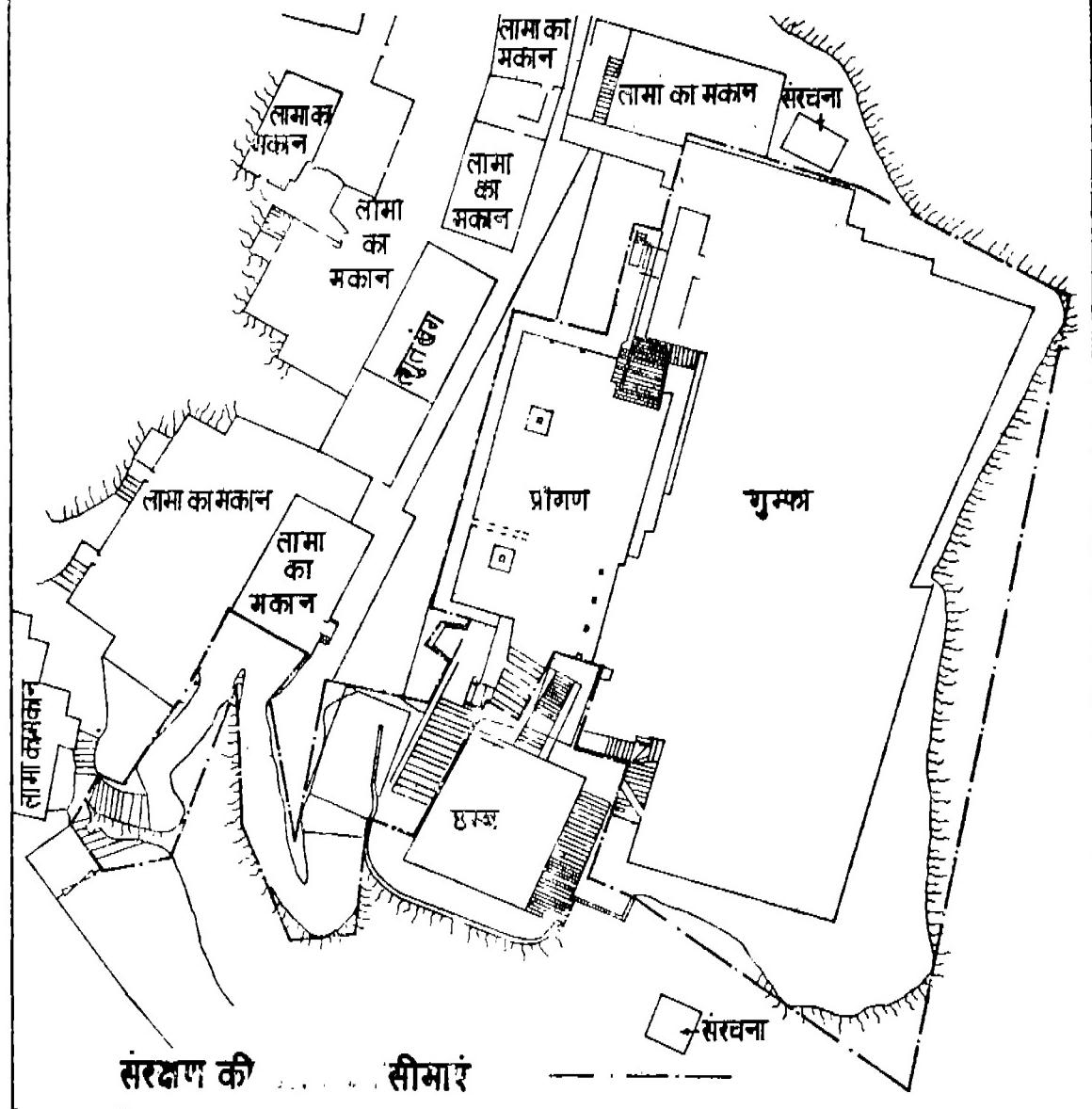
राज्य	जिला	तहसील	प्रबलेप	संस्मारक का नाम	संक्षय के अधीन सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व प्लाट संख्याक्रम	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू-काश्मीर	लद्दाख	सेह	ठिकसी	जैसाकि नीचे प्रस्तुत स्थल रेखांकन में दर्शित है, सर्वेक्षण प्लाट से 2040 के बाद की भूमि के साथ सगी हुई प्राचीन गुफा	नीचे प्रस्तुत स्थल रेखांकन में दर्शित सर्वेक्षण प्लाट से 2040 का भाग	0.3172 हेक्टेयर

सीमांड	स्वामित्व	टिप्पणी
8	9	10
उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट से 2040 का लेच भाग	निजी स्वामित्वाधीन	गृहा धार्मिक उपयोग में।
पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट से 2040 का लेच भाग		
दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट से 2040 का लेच भाग		
पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट से 2040 का लेच भाग		

थिकसे, जिला लैठ(लद्दाख) में स्थित प्राचीन गुम्फा का स्थल मानवित्र

0 6 12 18 24 30 मीटर
0 20 40 60 80 100 फुट

3.



DEPARTMENT OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
New Delhi, the 23rd December, 1985
(Archaeology)

said notification was affixed in a conspicuous place near the said monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

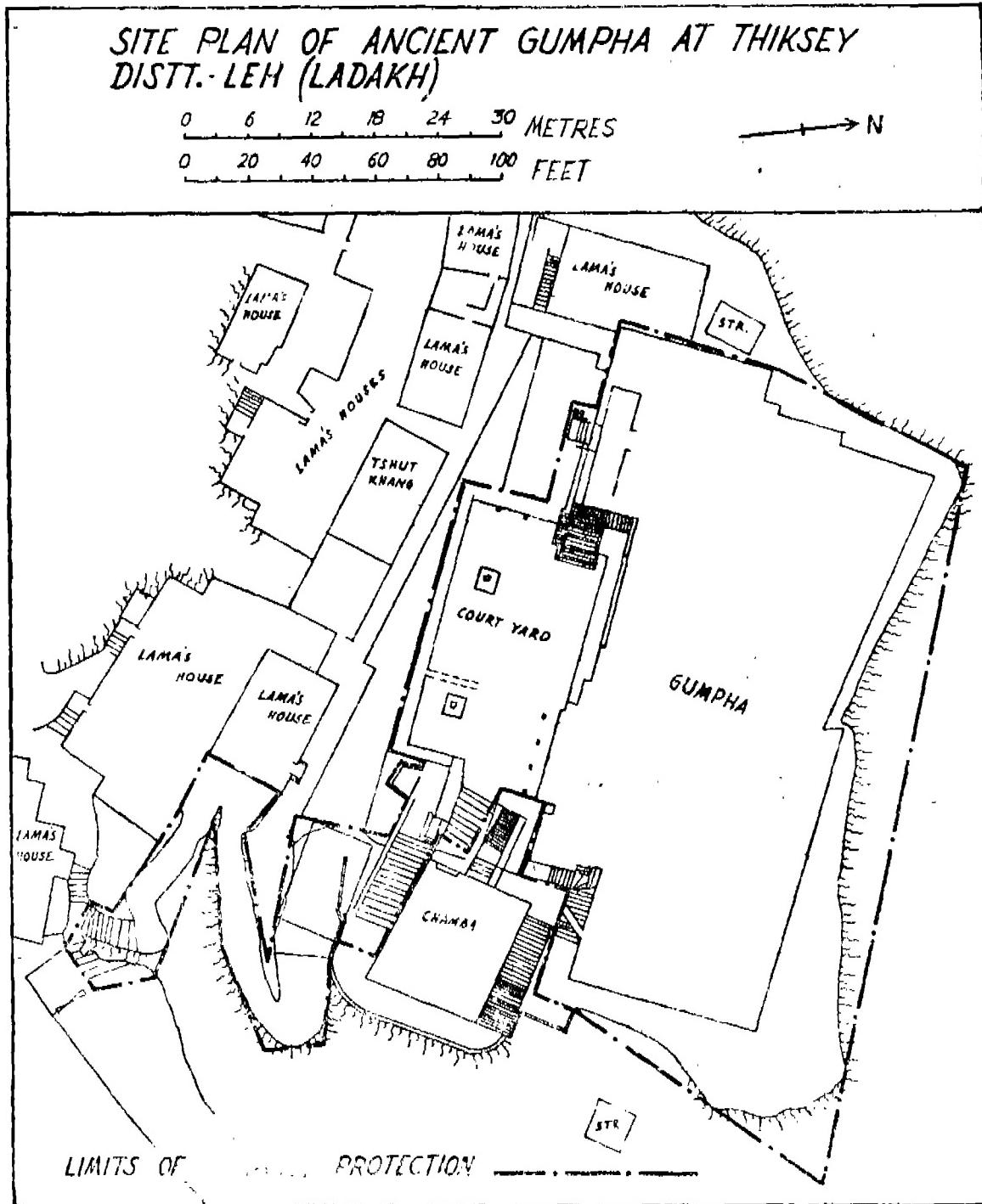
And whereas, the said Gazette was made available to the public on the May, 1985;

And whereas, no objection from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot number included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu and Kashmir	Ladakh	Leh	Thiksey	Ancient Gomphpa alongwith part of land comprised in part of survey plot No. 2040 as shown in the site plan reproduced below	Part of survey plot No. 2040 as shown in the site plan reproduced below	0.3172 hectares	North:— Remaining portion of survey plot No. 2040 East.— Remaining portion of survey plot No. 2040 South.— Remaining portion of survey plot No. 2040 West.— Remaining portion of survey plot No. 2040	Privately owned	Gomphpa in religious use.



[No. 2/16/80eM]

का या १०८.—केन्द्रीय सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और प्रवर्षेष प्रधिनियम, 1958 (1958 का 24) की घारा 4 की उपचारा (i) के अधीन भवेति के अनुसार, भारत सरकार के संस्कृत विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की एक अधिसूचना सं० का घारा २०७८ तारीख २७ अप्रैल, १९८५ द्वारा, जो भारत के राजपत्र, घारा २, खंड ३, उपलब्ध (ii), तारीख ११ मई, १९८५ में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की प्रगत्यांशी में विनियिष्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते के प्रपत्रे आधय की सूचना ही थी और उस अधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक के समीप एक भृजयुक्त स्थान पर लगा ही गई थी :

और उक्त राजपत्र जनता को १३ मई, १९८६ को उपलब्ध करा दिया गया था

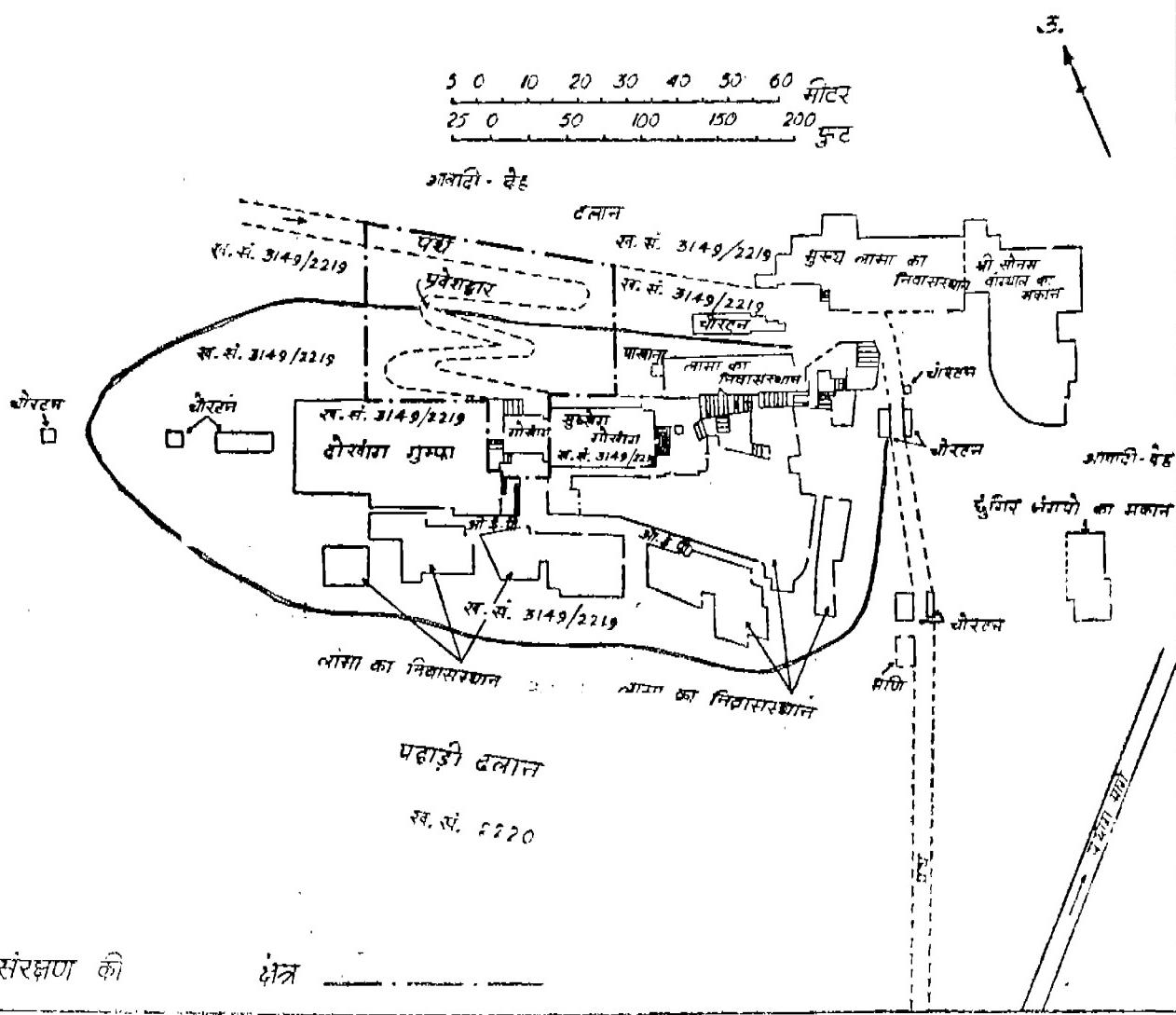
और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 4 की उपचारा (3) द्वारा प्रवत भवित्यों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय अनुसूची में विनियिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है ।

प्रसादी

राख	विभा	तहसील	अधेस्थान	मंस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन नम्बरिलित किये जाने वाले राजस्व प्लाट संख्याएँ	प्रेक्ष
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू-कश्मीर	लेह(लद्दाख)	लेह(लद्दाख)	प्लाट	जैसा नीचे प्रस्तुत स्थल रेखाक में दर्शाया गया है सर्वेक्षण प्लाट सं 3149/ 2219 के भागों से थने मास्तन थेव सहित बीड़ गुका	जैसा नीचे प्रस्तुत स्थल रेखाक में दर्शाया गया है प्लाट सं 3149/2219 के भाग	0.11 हेक्टर
सीमाएँ				स्वामित्व	टिप्पण	
	8			9	10	
उत्तर—सर्वेक्षण प्लाट सं 3149/2219 का थेव भाग पूर्व—सर्वेक्षण प्लाट सं 3149/2219 का थेव भाग दक्षिण—सर्वेक्षण प्लाट सं 3149/2219 का थेव भाग पश्चिम—सर्वेक्षण प्लाट सं 3149/2219 का थेव भाग	विजी		धार्मिक उपयोग में।			

बौद्ध गुम्फा, पर्यांग, तहसील-लेह, जिला-लेह (लदाख) का स्थल मानविक्र



संरक्षण की

५८

[सं० २/२८/८०-एम]

एम डास० नागराजाराव, महानिवेशक और पवेन संयुक्त सचिव

S.O. 99.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) S.O. No. 2078 dated the 27th April, 1985, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 11th May, 1985, the Central Government gave two months notice of the intention to declare the monument specified in the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the May, 1985;

And whereas, no objection from the public has been received by the Central Government;

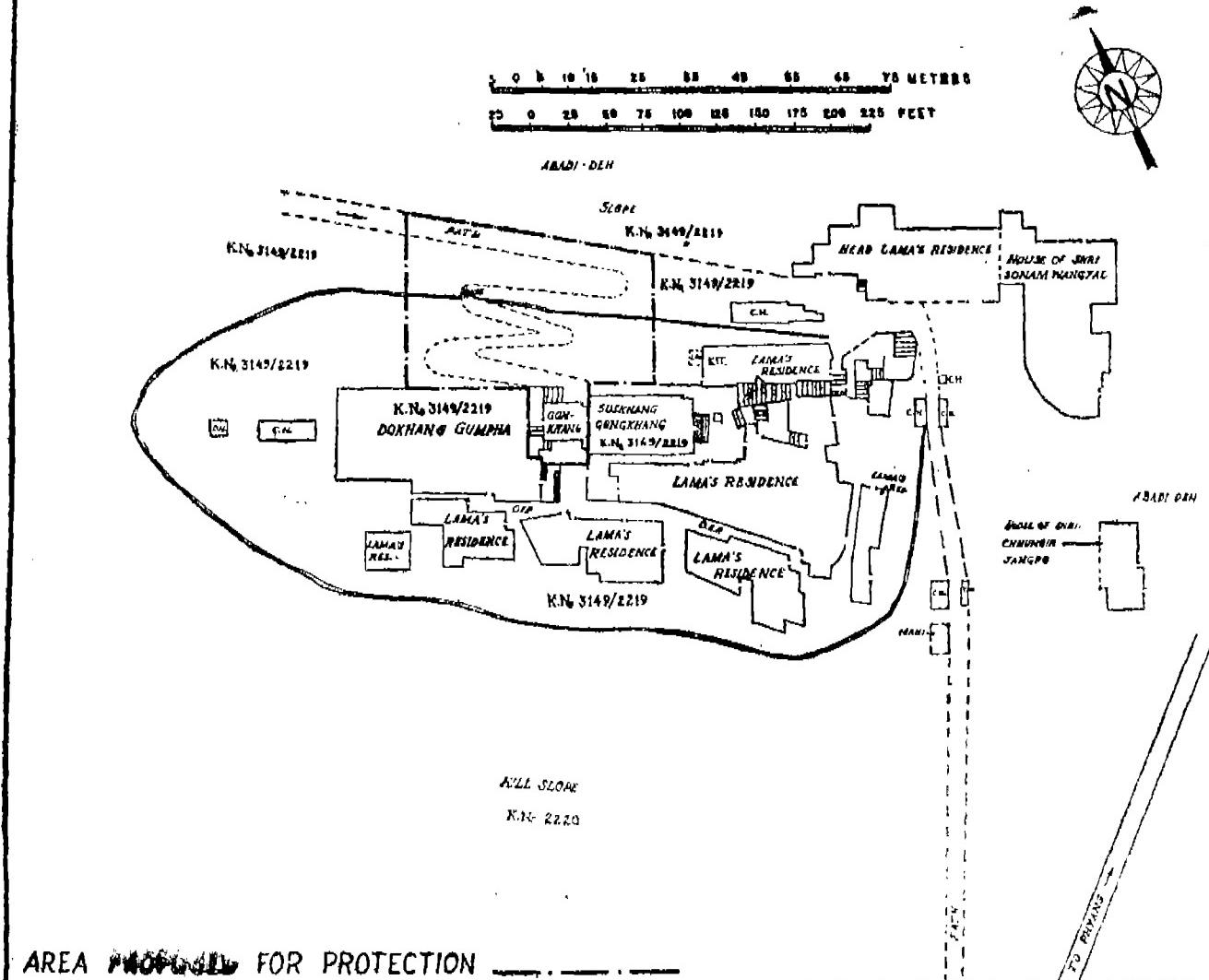
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot number included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu and Kashmir	Leh (Ladakh)	Leh (Ladakh)	Phyang	Buddhist Gumpa together with adjacent area comprised in part of survey plot No. 3149/2219 as shown in the site plan reproduced below	Part of survey plot No. 3149/2219 as shown in site plan reproduced below	0.11 hectares	North.—Remaining portion of survey plot No. 3149/2219 East.—Remaining portion of survey plot No. 3149/2219 South.—Remaining portion of survey plot No. 3149/2219 West.—Remaining portion of survey plot No. 3140/2219	Private	In religious use.

SITE PLAN OF BUDDHIST GUMPHA AT PHYANG, TEHSIL·LEH.

DISTT·LEH (LADAKH)



[No. 2/28/80-M]

M. S. NAGARAJA RAO, Director General and
Ex-officio, Jt. Secy.

हिन्दू संस्कृत प्रशासन

(द्रुसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1985

क्रा०प्रा० 100.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के
बाटू III के ऐरा(क) के प्रत्यासार महानिवेशक, द्रुसंचार विभाग ने
पञ्चलगुडी तथा तिरुचुली ईलोफोन केन्द्र, समिक्षालय में दिनांक
13-1-1986 से प्रभागित दर प्रजाती सागू करने का निष्पत्ति किया है।

[संख्या 5-32/85-पी एच बी]
के०पी० शर्मा, सहायक महानिवेशक (पी एच बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunication)

New Delhi, the 31st December, 1985

S.O. 100.—In pursuance of para (a) of Section III of
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced
by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General,
Department of Telecommunication, hereby specifies 13-1-1986
as the date on which the Measured Rate System will be
introduced in Pandalgudi and Tiruchuli Telephone Exchange,
Tamil Nadu Circle.

[No. 5-32/85-PHB]
K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

सरकारी विभाग

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985

का० आ० 101:—सैमर्ट इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, डाकघर-चोटामुरी, जिला रायगढ़ी (बिहार) (बी.आर./47) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतीक्षा उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपचारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का सम्मान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ऐसे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त जीवितों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचार अनुसूची में विभिन्न शर्तों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्थापन के सभी उपचारों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे सेवा रखेगा तभा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्पाद्य करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपचारा (3क) के छाड़ (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, सेवाओं का अनुबंध, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी घयों का वहम नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उक्त संशोधन की प्रति सदा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भावा में उक्तकी अनुभव वार्ता का अनुबंध, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का मा उक्त अधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले, ही भवस्य है, उक्तके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बोबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सहस करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधिनं पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध काफ़ी बड़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से विशिष्ट की जाने की अवसरा करेगा जिससे कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अन्दर अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस बात में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिग्राम/नामनिर्देशिती की प्रतीकरण के रूप में वोनों रकमों के अल्पर रकम का सदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संयोग्यन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा औह जहाँ किसी भी स्थोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बृहिकोण सपष्ट करने का युक्तियुक्त अवश्य करेगा।

9. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना लुका है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना लुका है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दर्भ में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न रही होती हो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के सदस्य का उत्तराधिक नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन प्राप्त वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्कावार नामनिर्देशिती/विधिक बारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण रूप की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/286/85-स०एस०-4]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd December, 1985

S.O. 101.—Whereas Messrs. Indian Aluminium Company Limited, P.O. Chotamuri, Distt. Ranchi (Bihar) (BR/47) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days, from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominate/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/286/85-SS.IV]

का. गा. 102—मैर्सर सैफुल हस्टोट्सट आफ ट्रॉप डिजाइन बालाकोश, हैदराबाद (ग. गी / 4022 पंड 104) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रबोधन उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पश्चक व्रजिताय या श्रीमियम का संदाय किये जिन ही, मार्गीय जीवन बीमा नाम की मामूलिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी तिक्केप महबूब बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उक्त अनुकूल हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदल विविधों का प्रयोग करने द्वारा और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहने द्वारा उक्त स्थापन को हीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेणिक भविष्य निधि अध्युक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणों भेजेगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा नथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुधिधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण घटानों का प्रथेक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के छंड (क) के अधीन समय-समय पर नियिष्ट करें।

3. मामूलिक बीमा स्कीम के प्रणाली में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणों का गस्तुन किया जाता, बीमा श्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतर्गत, निरीक्षण घटानों का संदाय आदि भी है, होते वाले सभी घटानों का अहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दीमा रतीम के नियमों की एक प्रति, श्रीर जब उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति नथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल्य वालों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई गोपा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक मामूलिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा श्रीर उसकी आवश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सम्बन्ध करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्बन्धित है से वृद्धि की जाने की अवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूलिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हैं।

7. मामूलिक बीमा स्कीम में किसी वात के होने द्वारा भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर डग स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम में कम है जो कर्मचारी की उम दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वार्तिम/नामनिर्देशिती की प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. नामहिक बीमा शीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अनन्द्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो जहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रवना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्थग्न करने का यक्षितपूर्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है, अधीन नहीं रख जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे विसरी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह जी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत शारीर के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्युपगत हो जाने वाला है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों ने नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उन स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को भूत्यु होने पर, भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाकृत राशि के तकदीर नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उम राशि का संदाय तत्त्वानुसार से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण रूप से की प्राप्ति के एक मानके भीतर नियन्त्रित करेगा।

[राज्या एस-35014/290/85-एम. एम-4]

S.O. 102.—Whereas Messrs. Central Institute of Tool Design, Balanagar, Hyderabad (A.P.) 4022 and 4404 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(290)/85-SS-IV]

का. आ. 103—गैर्ज टाटा प्रैम लिमिटेड, 414-बीर मावरकर मार्ग, प्रभावी, यमर्क-400025 (एम. एम/986) (जिसे इसमें हमके प्रत्यात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी संविष्ट निधि और प्रीर्क उप-वर्ग अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें हमके प्रत्यात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि इस स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संशय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम ने अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रखे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निष्क्रेप संशब्द बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके प्रत्यात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन्तर्भूत हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपाधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावधि अनुभूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपकरणों से प्रवर्तन से छूट देते हैं।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मार्ग की मापदित के 15 दिन के भीमर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपाधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालीन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियाँ का प्रस्तुत किया जाता, बीमा श्रीमियम वा' संदाय लेखाओं वा अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की मापा में उसकी मूल्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम से सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत दर्ज करेगा और उसकी बाबत साक्षण्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबल्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुबोध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के हांसे हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस नीम के अधीन संदेय रकम उन रकम से कम है जो कर्मचारी को उग दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिक्रिया के रूप में दोनों नक्कों के अंतर के बगवार एकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपकरणों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य, निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दूषिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणबन, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उग सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना नहीं है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह जाए सकती है।

10. यदि किसी कारणबन, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत सारीखे पे भीतर श्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता

है, तो प्रतिसीधी को व्यवस्था हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा श्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सूच संदर्भों के नामनिर्देशितीयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा फायदों के संदाय का उल्लंघनित नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितीय/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तहतरना में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक तात्पर भीतर सुनिचित करेगा।

[संघ एम - 35014/293/85-एम.एस.-५]

S.O. 103.—Whereas Messrs. Tata Press Limited, 414 Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400 025 (MH-986), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. 35014/293/85-SS.IV]

नई विस्तीर्ण, 26 दिसम्बर, 1985

का. आ. 104.—मेससे चन्द्रा ई कमटाइल स्कीमटेट, भिक्षु एरोड़स पोस्ट, कोयम्बतूर—14 (टी. प्र. 932) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-भव्य अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है :

आगे केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् भविष्यावाय या प्रीमियम का संदाय किये विना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी मिशेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुरूप हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रयत्न संबिलियों द्वारा प्रयोग करते हुए और इससे चपाचल अनुसूची में शिविरिण शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीन

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपलब्धों के प्रवर्तन दे छूट देनी है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक¹ प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्षण, तमिल नाडू को ऐसी विवरणिया भेजा जाएगा ताकि उक्त स्थापन के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिट करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास का समाप्ति के 15 दिन के भीतर सामाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर नियिट हों।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत सेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रमुख किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदर्भ, सेवाओं का ग्रांटरण, नियोक्षण प्रभागों का संदाय आदि जैसी हों, तो वाले मर्गों अपेक्षित वह नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वृद्धिश्वास की भावामें उनकी मुद्रा ताकि वालों का अनुशासन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 17 के अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्यों के रूप में उसका न.म. सुरक्षा दर्ज करेगा और उसकी बावजूद अग्रवाल की प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि का अपलब्ध कायदे ग्रहाएँ जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध पायार्दात् से तरुणित रूप से बढ़िया की जाने की ध्यास्था करेगा। जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुरूप हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में विसी बात के होते हुए ही, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से न भ है जो कर्मचारी को उस दिन में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिग्राहन/मनिवेशनी को प्रतिक्रिया के रूप में उसी रकमों के अंतर के अनुराग रकम का संदाय करेगा।

8. ग्रामीण बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि अनुरूप, तमिल नाडू के पूर्व अनुरोदित के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्राविकृत प्रभाव पहने की समावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुरोदित देने से पूर्व कर्मचारियों को आगामी दृष्टिकोण स्थाप्त करने का युक्तिपूर्व अवकाश देगा।

9. यदि किसी कारणात्मक स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने अपना चुका है, अवीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अवीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी जारीकारण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत सारीज के भीहर प्रीमियम का संदाय करने से अग्रकाल रहता है, तो कलियों को व्यपर्यास हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा श्रीमयम् के सदाय में किए गए विशी अस्तियम का द्वारा में, उत्तर सूखदार क तामनिर्देशितियों या विधिक वार्ताओं का जो अदि यह छृंक न दी गई होती ही उक्त स्थीम के अंतर्गत होते, श्रीमा कायदों के मंदाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।

12. इस नियम के अधीन आने वाले नियमों मध्यम की भूल्यु हुनि पर अस्त्राय जावन लाभ नियम, बीमाकृत गणि के हफदार नामनिर्वेणिय/ विधिक विधों को नन गणि का मंदाय नम्यता से और प्रयोक दाया पर हर प्रकार मे पूर्ण दावों की प्राप्ति के एक मास के भावतर गुनिष्ठित करेगा।

[प्राप्ति-मास-नियम-35014/295/85-SS.IV]

New Delhi, the 26th December, 1985

S.O. 104.—Whereas Messrs. Chandra Textiles Limited, Civil Aerodrome Post, Coimbatore-14, (TN)932 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance of premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme; the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum a/cured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/295/85-SS.IV]

का. आ. 103 —मैसेस किलोस्टर प्रीयूमेटिक्स कंपनी लिमिटेड, हउपमार हडस्ट्रीयल प्लॉट, पूर्ण-411013 (एम. ए-ए-3113) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमचारी भविष्य निधि और प्रकार्ण उपचाय अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) बीमा भाग 17 की उपचारा (२क) के अधीन उक्त दिन जने के लिए घोषित किया है;

आर केंट्रीय मरकार का मामाधान है। गया है कि उक्त स्थापन के कमचारी, किसी पृथक भविष्य या श्रीमयम का मंदाय किए बिना ही भरतीय जीवन योग, नियम की भास्तुक बीमा स्थीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे नठा रहे हैं और ऐसे वसंतार्थियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अविक अतुकूल हैं, जो कमचारी निषेष सहवाह बीमा स्थीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) के अधीन उक्त अनुसंधान हैं;

अतः केंद्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की भाग 17 की उपचारा (२क) द्वारा प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करने हुए और इसमें उपचार अनुसंधान में विविध शर्तों के अधीन उक्त उपचाय को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त भीमा के सभी उपयोगों के प्रबंधन में सह देती है।

अनुमूल्य

1. उक्त उपचार के नंबर में नियोजन: प्राविष्टक भविष्य निधि अनुग्रह, महाराष्ट्र को ऐसी निवरणगण के भेजेंगा और ऐसे नेत्रों ग्रहण सत्ता निरीक्षण के लिए ऐसी गृहिणी प्रदान करेगा जो केंद्रीय मरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमाणों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भावतर मंदाय रूपमा जो केंद्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की भाग 17 को उपचारा (२क) के खंड (क) के ग्राहीन गमय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. भारतीय बीमा स्थीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेडों का रखा जाना, विवरणियों का ग्रस्तुत किया जाना, बीमा श्रीमयम का मंदाय, नेत्राभासों का अंतरण, निरीक्षण प्रमाणों का साथाय यादि भी हैं, होने वाले सभी व्यायों का उड़न नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय राज्यकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के भूषण पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उचल अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पक्ष ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त अपेक्षा और उसकी बाबत आकर्षक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदर्भ करेगा।

6. यदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उसके स्कीम के अधीन अनुग्रह हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की भूत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में पांच दिनों तक, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी वे विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकरण के स्पष्ट में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धियों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रपना शनु-मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को मपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिस स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने काले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के पीछे प्रीमियम का संदाय फरसे में असफल रहता है, तो पालिसी को घ्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में, उन मूल सवासों के नामनिर्देशितीयों वा विधिक भारियों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उन्नरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने काले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाकृत गणि के हकदार नामनिर्देशितीय विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय लापता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार मूर्ख वाले की प्राप्ति के एवं माम के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/296/85-एस. पर-1]

S.O. 105.—Whereas Messrs. Kirloskar Pneumatic Company Limited, Hadapsar Industrial Estate, Pune-411013, (MH)3443 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life

Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of the employees who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/296/85-SS.IV]

का. अ: 108.—दैसमें आवश्य प्रदेश को-आपरेटिव सेवन समुदायवर चेन्नैमेड रैन रिमिटेड, वाराकोट्युरा, हैदराबाद (ए. पी./2505) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मध्यव्यं निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

ओर केन्द्रीय सरकार वा गमधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिकार या प्रीमियम का संदाय किए, बिना वी, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे ना कारबंदी ने प्रतिक प्राप्त हैं, जो उक्तवारी नियोजित सहवास बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के अधीन उक्त प्रक्रिये हैं।

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) हारा प्रदूषणकर्त्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायकूल अनुसूची में विलिष्ट गती के अधीन रहते हुए उक्त स्थापनको तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थापन के सभी उपमन्त्रों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के मध्य में नियोजित प्रावेशिक मध्यव्यं निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखना तथा नियोजन के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करें।

2. नियोजित, ऐसे नियोजन प्रभारों का प्रत्येक मायु की समाप्ति के 15 दिन के भीतर यात्रा करेगा जो केन्द्रीय सकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत (क) के अधीन संश्य-समय पर नियिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रभासन में, जिसके मन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, नियोजन प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले, गंभीर व्ययों का बहत नियोजक हारा किया जाएगा।

4. नियोजित, केन्द्रीय सरकार हारा अनुसूचित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाता, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बदुसंलग्नों की मापा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थान के सुनानापूर्व पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचार मध्यव्यं निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की सामूहिक बीमा स्कीम के मध्यस्थ के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को मंदित करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में गमनित हृषि से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेग- जिसमें कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक मनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में जिसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को उस पर इस स्कीम के अधीन मंदिर रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारों को उस दिशा में दिया जाता, जब वह उत्तर रकम के अधीन हूँता तो, नियोजित कर्मचारियों के विविध विविध नामनिर्देशियों वी प्रतिवार के रूप में दीजाएं रकमों के अन्तर के बाबत रकम का गंद पकड़ेगा।

8. 9. 1. गूदिट शीम, गूदिट के उपकरणों में कोई भी संगोष्ठी, भौतिक भवित्व निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुसूचित के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिहृत प्रभाव पड़ते की संसाचना हो वहाँ, परिसिर भवित्व निधि आयुक्त, अपना अनुसूचित देने से पूर्व कर्मचारियों को आता दिल्लीकोग स्वष्ट करेंगे का पुक्तियुक्त अवगत देना।

9. यदि किसी कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उप भागुहिक बीमा रकम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अवैत नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त हुए वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह जी सकती है।

10. यदि किसी कर्मचार, नियोजित भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियन तारीख के भीतर प्रभासन के संशय करते में अनुकूल रहता है, तो वह किसी जो अपार वा जाने दिया जाता है वो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजित द्वारा प्रीमियम के दृष्टि में किसी भी कर्मचारियों की नियमों के द्वारा में, उन नृत ग्रामियों के न नियमितियों के विविध विवरणों को जो यदि यह, छूट नहीं गई दौरी हो उक्त स्थापन के अन्तर्गत होते, बीमा कारबंदी के संदर्भ के उत्तम विवर नियोजित पर होता।

12. इस दिन के भीतर प्रत्येक जो किसी मद्दत की वृद्धि होते पर भारतीय जीवन बीमा नियम, भीमुकूल राणि के हुक्मदार नामनिर्देशियों/विविध विवरणों को ज्ञ राणि के सदाच तत्परता में आर प्रत्येक विवर में हर प्रकार में पूर्ण वाले की प्राप्ति के ऐक मायु के भीतर सुनिष्ठता करता।

■ न. एस-35014/297/85-एस. एन.-4।

S.O. 106.—Whereas Messrs. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Limited, Baraketpura, Hyderabad, (AP/2505), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.35014/297/85-55.IV]

का. आ. 107.—मैसर्ज जिन्दगी एल्युमिनियम पिमिटेड. 1/6वी, प्रागप-
प्राली रोड, नई फ़िल्मी-110002 (चौ. पन/3680) (जिसे इसमें इसके
पासात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि श्री प्रकीर्ण
उपबम्ब अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसके पासात्
उक्त अधिनियम कहा गया है) की भाग 17 की उपधारा (3क) के
अधीन छूट दिया जाने के लिए प्राप्त किया है।

पैर वेन्ट्रीय सरकार का समोद्धान हो यथा है कि उगा स्थापन के
रखाने री, किसी पृथक अधिनियम या प्राप्तिकाम का संशोधन लिए विना ही
पासात् शीघ्रता वीमा नियम की मालिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन
वीमा के रूप में पायदे ज्ञात रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ऐसे पायदे
उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी विशेष स्वतंत्र वीमा स्कीम,
1976 (जिसे इसके पासात् उक्त स्कीम का भाग है) के प्रवीन रहे
अनुचय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भाग 17 की उपधारा (2क)
(एक) द्वारा प्रश्न स्थितियों का प्रयोग करने हुए और इससे ज्ञात उ
शास्त्रम् भी से नियन्त्रण शर्तों के अधीन रहने हुए उक्त स्थापन को नोन
लाए की अधिकारी के लिए उक्त स्कीम के मध्य उपबम्बों के प्रवर्तन से सूट
देती है।

अनुमोदनी

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि
शास्त्रम्, दिल्ली को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा
निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रिताएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-
समय पर नियन्त्रण करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास नी समाप्ति के
15 विन के भीतर संबंध करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की
भाग 17 की उपधारा (3क) के छान्ड (क) के अधीन समय-समय पर
नियन्त्रण करें।

3. मालूहिक वीमा स्कीम के प्रणाली में, जिसके अन्तर्गत लेशामों
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाए, वीमा ग्रामियम का
संदाय, लेशामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, जोले
वाले मध्ये अपनी का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वीमा स्कीम के नियमों
की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमतें भी भाग में उसकी मुद्र्य आतीं जो
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त
अधिनियम के अधीन दृष्ट प्राप्त किये थे तथा उनकी भविष्य निधि वा पहले
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक,
ग्रामियक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा
प्रोत्त. उसकी बाबत अन्तर्याम प्रामियम भवानीय जीवन वीमा नियम का
संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध कायदे वाले
जाने हैं तो, नियोजक ग्रामियक वीमा स्कीम के अधीन नदी-पानी का
उपलब्ध कायदों में संशोधन एवं विविध की जाने की व्यवस्था करेगा
जिससे कि कर्मचारियों के लिए स मालूहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध
कायदे उन कायदों से प्रथम अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्तर्ये
हैं।

7. समूहिक वीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यार किसी
कर्मचारी का सूत्र पर उग स्कीम के अधीन संदेश रकम इस रकम से कम
है जो कर्मचारी का उस दणा में संदेश होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन
होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वार्षिक नामनिर्देशिकी को प्रतिक्रिया
ने अप में दोनों रकमों के अन्तर के बाबत रकम का संदेश करेगा।

8. समूहिक वीमा स्कीम के उपबम्बों में कोई भी संशोधन, प्राप्तिकाम
भविष्य निधि, आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा;
आगे जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के लिए पर प्रतियुक्त प्रभाव पड़ने
की संभवता हो वहाँ, प्राप्तिकाम भविष्य अनुकूल, अपना अनुमोदन देने
से पूर्व कर्मचारियों को अपना उनिकोण स्थाप्त करने का व्यक्तियुक्त अवगत
देगा।

9. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस समूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना लुका है, अधीन नहीं रख जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कार्यवे किसी रौटिसे कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी भारतीय नियोजन का अधीन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्राप्तियम का संदर्भ करने में अपराध रहता है, और पालिसी को अपराध हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रभियम के संदर्भ में फिर पाए किसी अधिकारी की वक्ता में, उन मृत मर्दसां के नामनिवेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दा गई हैं तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कार्यवे के संदर्भ का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बासकृत रक्षा के हक्कदार नामनिवेशिती/विधिक वारिसों को उस रक्षा का मंदिर तत्वरूप से और प्रत्यक्ष दशा में हर प्रकार से पूर्ण बाबे का प्राप्ति के एक मासके भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एम-35014/298/85-एस. एस-4)]

S.O. 107.—Whereas Messrs Jindal Aluminium Limited, 1/6B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002, (DL/2680), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/298/85-SS.IV]

का. आ. 108—मैसर्स जिव्हल अस्युमिनियम लिमिटेड, 641, प्रसाद चैम्बर्स स्ट्रेटेजी मिल कम्पाउण्ड, वर्क्स-400004 (एस.एस. 15903) (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उपचारन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के उपचारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अधिकार किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समावास हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् भविष्य या प्रीभियम का संदर्भ किए जिन भारतीय जीवन बीमा नियम की सामृद्धि बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कार्यवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कार्यवे उन कार्यवों से अधिक भन्नकूल हैं, जो कर्मचारी निषेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें प्रदत्त हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रबत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचारा इन्सुची में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अधिकि के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपचार्यों के प्रशंसन से छूट देती है।

अनुभूति

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाप्रशास्त्र को एसो विवरणिया भेजेगा और ऐसे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केवल य सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के अंतर सम्बाध करेगा जो केवल य सरकार, उक्त भविष्यनिधि की आरा 17 की उपचारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अनुरूप लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संबंध, लेखाओं का अध्यक्षरण, निरीक्षण प्रभारों का सम्बाध आदि भी है, हाले वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केवल य सरकार द्वारा अनुभूति बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति संथा कर्मचारियों की बहुसंघट्य की भाषा में उसकी मुद्य बातों का अनुबोध स्थापन के फूलना पटट पर प्रतिक्रिया करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या इस भविष्यनिधि के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पूर्ण सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षा दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सम्बद्ध करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाएं जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में सम्बुद्धि रूप से कृषि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबोध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सुन्दर रूपमें उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उस वाया में रखें होता जब उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिता / नामनिरेशिती को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रूपमें का सम्बाध पड़ेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बजाए नहीं दिया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिस्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रूप से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संबाध करने में असफल रहता है, भारतीय जीवन बीमा नियम को व्यापत हो जाने किया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्बाध में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की वाया में, उन मृत सदस्यों के नामनिरेशितीयों या विधिक वारितों को जो यदि यह छूट त दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के सम्बाध का उत्तरवायित नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन भारते वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाहात राशि के हकदार नामनिरेशितीयों / विधिक वारितों को उस राशि का संबाध तत्परता से और प्रत्येक वाया में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर गुनिश्चित करेगा।

[संलग्न एम- 35014/299/85-एम एम-4]

S.O. 108.—Whereas Messrs Jindal Aluminium Limited, 416, Prasad Chambers, Swedeshi Mill Compound, Bombay-400 004, (MH/15903), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/299/85-SS.IV]

का. भा. 109--मैसर्स विजयहस्थरी टेक्सटाइल लिमिटेड, पुलियाम-पेट्टी, (वाया)पीलाची- कोयम्बतूर जिला (टी.एन./1097) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार का समाधान ही गया है कि उक्त स्थापन के कमंचारी, किसी पृथक अधिदाय या अधिनियम की स्थापन किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उड़ा रहे हैं और ऐसे कमंचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कमंचारीनियों सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें प्रदूषित हैं;

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए और हास्ते उपबंध अनुसूची में विविध शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को वैभव की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रबंधन से छूट देती है।

भनुमतों

1. उक्त स्थापन के तीनों में विवाह प्रारंभिक भविष्य निधि आयुक्त, तनिं नाडु का ऐसा विवरणियां भेजेगा और पैसे लेखा रखेंगा तथा विवाह के तिर दोनों गुप्तियां प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे विवरण प्रभारी का प्रत्येक मास के समाप्त के 15 दिन के भाँति उक्त स्थापन को केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रयोगन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा, जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संशोधन, निवाप्रांतों का अन्तर्गत, विवरण प्रभारी का सन्वाद आदि भी है, हीमें वाते मध्य अप्यों का बहुत नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जड़ कर्मी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वटुमंठया की सापेक्ष में उसकी मूल्य बातों का प्रयुक्ति, स्थापन के सूत्रपट पर प्रवर्गित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि ना गा उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका भाग तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सम्बत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुक्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक प्रारूप हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्बेद रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में भवित्व होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता है, तो उक्त गार्डरों के प्रिंटिं वारिस / नामनिवैशिरी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के अन्तर रकम का सम्बाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रारंभिक भविष्य निधि आयुक्त (तमिल नाडु के पूर्व अनुपोदत के दिन नहीं किया जाएगा और जड़ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रारंभिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी दारणावासा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी दारणावासा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के अन्तर प्रभावित भा. तस्वीर करते में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवात हो जाता है तो छूट रद्द को जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दर्भ में किए गए किसी घटत्रिक की बात में, उन मृत सम्बन्धों के मामनिदोषितियों या विधिक वालियों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कॉम के अस्तित्व होते, वीमा कार्यत के सन्दर्भ का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. इस स्कॉम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, योगानुकूल राशि के हुक्मादार माम निर्देशिती/विधिक वालियों का उस राशि का संबंध तत्परता से अंतर प्रत्येक दशा में हर प्रकार संपूर्ण दावे का प्राप्ति के एक भास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 / 300/85-एस. एस - 4]

S.O. 109.—Whereas Messrs Vijayeswari Textile Limited, Puliampatti, (Via) Pollachi-Coimbatore District, (TN/1097) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employer as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/300/85-SS. 1V]

का. आ. 110:—प्रैसर अंगरसोल—रैप्ट (इंडिया) लिमिटेड, महै चेन्ऱर हाउस, एस. के. अंगूरी मार्ग, वार्ली, अम्बई—400025 (एम. एच./4099) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपलब्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की ओर 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिया जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का सम्मान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिनियम का सन्दर्भ किए जाना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सापूर्णिक योग्यासीम के अंतर्गत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी के लिए ये फायदे उन फायदों से भविक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निष्क्रिय सहभाग बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के प्रबंधन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की ओर 17 की उपधारा (2क) ओर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और इसे उपायदृष्टुपूर्वी में वित्तियिक शर्तों के प्रयोग रद्दों हुए उक्त स्थापन को लीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तम स्तर के सभी उपयोगों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुमूल्य

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मदुराराष्ट्र और ऐसी विधियाँ जैसों और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारीों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उस प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के अन्तर्गत (क) के प्रधीन ममता-समय पर निरिट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालीन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा श्रीमियम का सन्दाय, ऐसाओं को प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारीों सन्दाय आदि भी हैं, जोने वाले सभी व्ययों का इन्हन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंघर्ष बीमा से उसकी मूल्य बानों का अनुबाद, स्थापन के मूल्यान्पृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त विस्तो स्थापन की भविष्य-मिधि का पहले ही सम्म नहीं है, उसके स्थापन में निवेशित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के मद्दस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बदल करेगा और उनकी वाक्ता आवश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सन्वाद करेगा।

6. यदि इन स्कीम के नवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे देना चाहते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन सप्तवध्य कायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के शब्दों अनुकूल हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी घात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उक्त रकम से कम है जो कर्मचारी को उस घात में संशेष्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विशिक वारिस/सामिलिंगिती की प्रतिकर के रूप में हाँतों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्माय करेगा।

8. गामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और यह किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो गहरा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना इटिकोन संष्ट करने का युक्तियुक्त असहाय देगा।

9. यदि किसी कारणवस्तु, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना लूका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवस्तु, नियोजक भारतीय जीवन नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर श्रीमियम का संवाद करने में असफल रहता है, तो पालिसी को अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा श्रीमियम के संवाद में किए गए किसी व्यातिक्रम की वक्ता में, उन मृत्यु सदस्यों के नामनिर्विवितियों पर विशिक वारिसों को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संवाद का उत्तरवायिक नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के प्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बायाहत राशि के तुकदार नामनिर्विवितियों/विशिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्पत्ता से और प्रत्येक दशा में तुर प्रकार से पूर्ण राशि की प्राप्ति के एक भाग के भीतर मूलिकता करेगा।

S.O. 110.—Whereas Messrs, Ingersoll-Rand (I) Limited, May Baker House, S. K. Ahire Marg, Worli, Bombay-400025, (MH)4099 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees'Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/301/85-SS. IV]

का. आ. 111.—मैसर्स साउथ इण्डिया विसकोस लिमिटेड, रेसकार्स, कोयम्बतूर (टी. एन./3323) और मिलमुगई पोस्ट आफिस कोयम्बतूर (टी. एन./3323) में स्थित कारखाना सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिनाय या प्रीमियम का संशय किए जिन ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में प्राप्त हुए और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन काश्त्रों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहमत बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उम्मेदनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्राप्तुकृति

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के सिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्भाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का सम्भाय, लेखाओं का अस्तरण, निरीक्षण प्रभारों सम्भाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहु नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अनुमत्या की भाषा में उसकी मूल्य भासों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई देस कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सम्भव है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के हृषि में उसका माम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी वादत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में सदृचित हृषि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हृषि होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सम्बेद रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश हुआ तो, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन हाता ता, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिक्रिया के हृषि में दोनों रकमों के प्रधीन उपलब्ध रकम का सम्भाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पहले की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणावश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना दुकान की धारीन नहीं रख जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणावश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियन्त तरीके भीतर प्रीमियम का सम्भाय करने में असफल रहता है, तो प्रतिवारों को व्यवरत हो जाने दिया जाता है छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्भाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में, उन मूल सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को भी पर्याप्त छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के प्रत्यंगत होते, बीमा कायदों सम्भाय का उत्तरवायित नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के प्रधीन-न्याने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्कावार नामनिर्देशिती/विधिक बारिसों को उस राशि का संवाद तत्प्रता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/302/85-एस. एस.-4]

S.O. 111.—Whereas Messrs South India Viscose Limited, Race Course, Coimbatore (TN/3323) and its factory at Sirumugai, P. O. Coimbatore (TN/3323-A), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/302/85-SS. IV]

का. आ. 112.—मैसरे हिन्दुस्तान लीकर लिमिटेड 63-गाउंड रोड, कनकना 700024 (इल्यू. वी./1198) और (1) आंबोन रोड, कलकत्ता (इल्यू. वी./192) (2) हालदिया, (इल्यू. वी./192) और (3) शामनगर (इल्यू. वी./682) में स्थित गोदाओं सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपधारा अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान ही गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्यावाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की गामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहमद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें प्राप्त हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का वर्णन करते हुए और इससे उपायदृष्टि सुनिश्चित शर्तों के व्यापार रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अधिकारीता के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपधाराओं के प्रदर्शन से छूट देती है।

अनुमूल्य

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रबोधिक भविष्य निधि प्राप्ति परिवर्तन बंगाल को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोत्तर के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भोतर मध्यात् करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अस्तंगत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सम्बाध लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सम्बाध आदि भी है, होमे वाले सभी व्यापों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की मापा में उसकी मुश्किलाओं का अनुवाद, स्थापन के मूल्यान्पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सवाल है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्केप्ट में उगाका नाम मुद्रित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सन्वत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे देते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था दर्ज करेगा जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुग्रहीत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम हो जो कर्मचारी को उस रकम में गणेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिवैधिति को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के प्रमाणर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त परिवर्तन बंगाल के पूर्व प्रानुसारण के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आना प्रानुसारण देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृद्धिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्बाध में विए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मूल सवार्थों के नामनिवैधितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रमाणर होते, बीमा कार्यों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन-माने वाले किसी सदस्य के मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाहृत राशि के हकदार, नामनिवैधिति/विधिक वारिसों की उस राशि का संबाध तत्परता से और प्रत्येक रकम में हर प्रकार से पूर्ण रूप से की प्राप्ति के एक भास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/303/85-एस. एम-4]

S.O. 112.—Whereas Messrs. Hindustan Lever Limited, 63, Garden Reach, Calcutta-700024 (WB/1198) including its branches at (1) Brabourne Road, Calcutta (WB/192) (2) Haldia (WB/192) and (3) Shambagar (WB/682), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the non-inheritor heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/303/85-SS. IV]

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1985

का. श्रा. 113—मैमै सामने रेकमटाइलम अमिटेंड 59-बी, बैकटा-स्ट्रीट रोड, दिल्ली, प्रम. पुरस्त, ओयलस्टर्ट-३ (टी. एन. 1937) (जिसे इसमें उसके पश्चात उस स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पक्षीय उपलब्ध व्यक्तियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उस स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपाधा (2क) के अधीन छूट दिय जाने के लिए आवश्यक किया है;

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिनमें पूर्व शासनियां या श्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जनजन वैभागिक नियम के मानुषिक वैभाग सर्कार के अधीन जनजन वैभाग के रूप में कायदे उठा रहे हैं और इसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी नियम सहमत वैभाग सर्कार 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्थान कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमत हैं।

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की वारा 17 की उपचारा (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचारा अनुसूची में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की रूपन अवधि के लिए उक्त सर्कार के द्वारा उपकार्यों के प्रबल्लन से कूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियन्त्रणालय को ऐसी विवरणीय भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा नियन्त्रण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे नियन्त्रण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के अंतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की वारा 17 की उपचारा (अ) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर नियिष्ट करें।

3. मानुषिक वैभाग सर्कार के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणीयों का प्रमुखत किया जाता, वैभाग प्रेमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गत, नियन्त्रण प्रभारों मध्य व्याप्रि भी है, होते वाले मर्यादयों के बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वैभाग सर्कार के नियमों के एक प्रति, और अब कर्मचारी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति नियन्त्रण कर्मचारियों की अनुसूचियों की भाष्य वालों का भाष्य में उसकी मुख्य वालों का अनुबाद, स्थापन के शूकना पद्धत पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक मानुषिक वैभाग सर्कार के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्जन करेगा और उसके वाले व्यापक प्रमियम भारतीय जनजन वैभाग नियम की संदर्भ स्थापन करेगा।

6. यदि उक्त सर्कार के अधीन कर्मचारियों को उपचार फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक मानुषिक वैभाग सर्कार के अधीन कर्मचारियों को उपचार फायदों में समुचित रूप से बढ़िया करने के लिए क्यवित्या करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मानुषिक वैभाग सर्कार के अधीन उपचार फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त सर्कार के अधीन न अनुमेय हैं।

7. सामियम वैभाग सर्कार में विवरणीय को होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस सर्कार के अधीन रखने उन रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वाला में सरेण्ट/एर, जब वह उक्त सर्कार के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचार के विविध वार्षिक/नामियोंषिट के प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बगवार रकम का यात्रा करेगा।

8. मानुषिक वैभाग सर्कार के उपचार फायदों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियन्त्रणालय के पूर्व अनुमोदित वैभागिक विभाग नहीं किया जाएगा और उन्होंने किसी संशोधन से नियन्त्रणालयों के हाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आयुक्त अनुमोदन वैभागिक विभागों को अनुना दृष्टिकोण से उनकी कायदाओं पर ध्यान देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जनजन वैभागिक नियम को उस सामूहिक वैभाग सर्कार के जिसे स्थापन पहले अपना शुक्रा है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस सर्कार के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रूप से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जनजन वैभाग नियम द्वारा नियन्त्रण सारिख के भीतर प्रेमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को अवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रेमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम/नियोजितों वा विविध वार्षिकों को जो अद्य तह, छूट न दि गई हो, तो उसका नहीं के अंतर्गत होने, वैभाग वायदों के संदाय का उत्तराधित्व नियोजक पर होगा।

12. इस सर्कार के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जनजन वैभाग नियन्त्रण वैभागिक राशि के हक्कावार नामितदर्शिता/व्यविधिक वार्षिकों को उस राशि का नवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण बाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[पंक्ति नं. 35014/311/35- एस. एस- 4]

New Delhi, the 27th December, 1985

S.O. 113.—Whereas Messrs. Southern Textiles Limited, 59-B, Venkataswamy Road, R. S. Puram, Coimbatore-2 (TN/937) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said Establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(311)|85-SS. IV]

का. प्रा. 114--मैसर्स वि बैलारी जिला को-आपरेटिव सीट्स बैंक लिमिटेड नं. 5399-होमपेट-583201, जिला बैलारी (के. एन. 13009) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्याय या ग्रीमियम का संदाय किए जाना है, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकृत हैं, जो कर्मचारी निषेप महबूद बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमति देते हैं।

प्रक. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विविध शर्तों के अधीन इन्हें हुए उक्त स्थापन को हीन वर्ष

की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपयोगी के प्रकार से छूट देते हैं।

प्राप्ति:

1. उक्त स्थापन के नंबर में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि शामुक कर्ताक को ऐसी विवरणियां देंगे और ऐसे लेख रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी मुविधाएँ प्रवान करेगा जो केवल य सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास के स्थानित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केवल य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के बंद (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखार्थी का रखा जाना विवरणियों का प्रत्युत किया जाना, वी.मा ग्रीमियम का संदाय लेखार्थी का अन्तर्गत निरीक्षण प्रभारों मध्यां आदि भी है, होते वाले मध्यों वर्षों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की प्रति प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस अंशोधन की प्रति वी.मा कर्मचारियों की बहुतेवढ़ा की धारा में उसके मूल जारी का अनुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रत्येक करेगा।

5. यदि कोई दो कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त स्थिरियम के अधीन छूट प्राप्त किए रखाये जाने की भविष्य निधि का पहले ही पदस्थ है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के स्वर में उसका नाम तुरत दर्द करेगा और उसके बाबत ग्राम्यक ग्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को अन्वत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध कार्यदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उत्तम कार्यों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कार्यदे उन कार्यों से अधिक प्रभुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्येह हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी गर्भाचारी की पृथु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उपर रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक के विधिक वारिस/नाभनिर्देशिक, क. प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के शंखर के बदावर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आपूक कर्ताक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जब किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहले की संमानना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आपूक, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिक्षेप स्पष्ट करने का युक्त अनुभव देंगे।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिस स्थापन पहले अपना छूटा है, या इस स्कीम के शायं न कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कार्यों रीति से कर हो जाने हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत सारंख के भीतर प्रभित्य का संदाय करने में असफल रहता है, तो प्राप्तिकों को अधिकत हो जाये दिया जाएगा है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रभियम के संदाय में किये गए किसी अधिकार के द्वारा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न हो गई हैं तो उक्त स्वर्ग के अंतर्गत होते, वे मृतकों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्वर्ग के उत्तरदायित्व के द्वारा जिस सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जनजन बोमा निगम, राजकृत राजा के हृषदार नामनिर्देशियत/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय उत्पत्ति से और प्रस्तेक दशा में एक प्रकार से पूर्ण बाबू के प्राप्ति के एक मात्र के अंतर सुनिश्चित करेगा।

[रिक्ता एस- 35014/312/85- एस. एस- 4]

S.O. 114.—Whereas Messrs. The Bellary District Co-Operative Central Bank Limited, No. 5398, Hosret-583201, Bellary District (KN/3009) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employer as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/312/85-SS. IV]

का. आ. 115.—पैसर्स बोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, नामिक दिव्वीजन, 75, इण्डस्ट्रील एस्टेट, सन्तुर-नामिक-422007 (एम. एच./12053), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्य या प्रीभियम का संदाय किए बित्ता ही, भारतीय योजन बीमा नियम को सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन योजना के रूप में कायदे बढ़ा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से भविष्यक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी नियमें सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन रूप स्थापित किये गये हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इसे उपायद्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट पारों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य मित्रि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर विद्युत करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की समर्पित के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन समय-समय पर विविष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का भलारण, नियोजक प्रभारी का सन्दाय प्राप्ति भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुनियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के व्ययों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त भविष्यनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्यनिधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहुए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की भविष्यत करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुरूप हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी दशा के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदैय रकम उरु रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदैय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बाराहर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धियों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व भन्नोदत के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, भन्नोदत दोनों से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का दृक्षिण्यकृत भवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने विधा जाता है तो छूट रह जी जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तराधित नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी रातस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, भीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्वेशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[रि. एग-35014/314/85-एस. एस.-4

S.O. 115.—Whereas Messrs. Motor Industries Company Limited, Nasik Division, 75, Industrial Estate, Satpur, Nasik-422007 (MH12053) (hereinafter referred to as the

said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employer as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the non-nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/314/85-SS. IV]

का. आ. 116.—मैसर्स इंस्टर्न एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 मोर 2 इण्डियन एस्टेट, गोविंदपुरा, भोपाल-462023 (एम. पी./1528), (जिसे इसमें हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की द्वारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिकारी या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए मेरे फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निवेदित सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उक्त अनुबोध हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की द्वारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त क्षमितयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबंध अनुकूली में विनियोग शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को सीन बर्ध की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त भव्य प्रदेश को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रयोग मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्भाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की द्वारा 17 की उपधारा (अ) के खण्ड (क.) के अधीन समय-समय पर नियिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ग्रन्तीत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का असरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यर्थों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की ग्रहणक्षम्य की धारा में उसकी मुख्य भांतों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-प्रदान पर प्रयोगित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अविष्य-निधि का पहली ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सम्बन्ध रखेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिनसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुरूप हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी भांति के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश होती, जब वह उक्त स्कीम के मध्यीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक यारिस/नामनिवेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के ग्रन्ति रकम के सम्बन्ध करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त, भव्य प्रदेश के पूर्व ग्रन्तीवादन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते की संभावना हो वहां, प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त, ग्रन्ता ग्रन्तीवादन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रन्ता दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिपूर्वक अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले ग्रन्ती चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को ग्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर ग्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा ग्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की विवरणों के नाम निर्देशितीयों या विधिक यारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के ग्रन्तीर्थ होते, बीमा कायदों के सन्दाय का उत्तरवायिक नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य के मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाइक्ट राशि के हक्कदार नामनिवेशिती/विधिक यारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक विवरणों के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/310/85-एम. एस.-4]

S.O. 116.—Whereas Messrs. Eastern Air Products Private Limited, 1 & 2, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal-462023(M.P.)1528) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014 (310)|85-SS. IV]

का. घा. 117.—मैसर स्टें फ्रेना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मं. 12, रामा हृष्ण रोड, सलेम-7 (टी. एन./7460), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की आरा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए जावेदान किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् भविदाय मा प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी नियम सहृदय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उहैं अनुबंध हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की आरा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए और इसे उपावद्ध अनुसूची में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन बर्ष की अधिक के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रबंधन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य निधि दायुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेजा रखेगा तथा नियोजन के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारों का अत्यधिक भास की समाप्ति के 15 दिन के भौतिक भान्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की आरा 17 की उपधारा (3क) के बाहर (क) के अधीन सम-समय पर नियिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तर्गत, नियोजन प्रभारों का सन्दाय भावि भी है, होने वाले सभी अपें का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भावा में उसकी मुर्ख बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत भ्रावशक्त प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सम्बद्ध करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुक्त रूप से बृद्धि की जाने की अवधारणा करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबंध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी के मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वजा में संदेश होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के प्रत्यक्षर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हों कि संभावना हो वहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अधिकार देना।

9. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, प्रधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले काफ़िरे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणबाट, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिती को अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रेमियम के संदाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में, उन मृत शदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न हो गई होती हो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कार्यों के संदाय का उत्तराधिकार नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाहत राशि के हक्कदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में दूर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिष्ठित करेगा।

[संख्या एस-35014/313/85-एस. एस-4]

S.O. 117.—Whereas Messrs. Anna Transport Corporation Limited, No. 12, Rama Krishna Road, Salem-7 (TN/7460) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such return to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu; maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assistance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014 (313)185-SS. IV]

का. ना. 117 —संख्या एस. एस. एम. लिमिटेड, पटियाला रोड, नाडा (पी. एस./1741), (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकारीं उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की द्वारा 17 की उपचार (क) के अधीन छूट दिया जाने के लिए प्राविद्यन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समझान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, फिसी पृष्ठक अधिकारी या प्रीमियम का सन्दाय किए जिन हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निषेच संबंध वाला स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उग्रह अनुशेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त स्थापन की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त अधिकारी भाग प्रयोग करते हुए और इससे उपायद अनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अधिक के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक अधिकारी निधि अनुमति वंजाव को ऐसी विवरणियां देंगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा ताथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त स्थापन की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अस्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी अवयों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंघया की भाषा में उसकी मुद्रण शर्तों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी, जो कर्मचारी अधिकारी निधि का या उक्त स्थापन के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिक्षय-निधि का पहने ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेग और उसकी बाबत अधिकारी प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सम्बत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे देते होते हुए भी, यदि किसी अधीन कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन अन्देय रकम उस रकम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/मामनिवेशीत की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन अन्देय रकम उस रकम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/मामनिवेशीत की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपवर्त्ती में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक अधिकारी निधि आनुबूद्धि अधिकारी के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएग और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिक्रिया अस्त

पड़ने की संभावना ही वहाँ, प्रादेशिक अधिकारी, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृद्धिकोण स्थाप्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना अनुकूल है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो यह छूट की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए, किसी अवित्तिकम को देश में, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तराधिक नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्कार नामनिवेशी/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हुए प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर पुनिविष्ट करेगा।

[भंगा एस-35013/309/85-एम. एस-4]

S.O. 118.—Whereas Messrs. H.M.M. Limited, Patiala Road, Nabha (PN/1741) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employee's Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/309/85 SS. IV]

का. आ. 119—मैसेंजर इनिवेस्टिमेंट इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, एलाट नं. 21-22 बेचटर-25, फरीदाबाद (पी.एम./4853) (जिसे इसके पश्चात् उनका स्थान कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपलब्ध अधिनियम 1952 (1952 का 14) जिसे इसमें इसके पश्चात् उनका स्थान कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (3क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार की समाक्षात् हुई गया है कि उनका स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिकार या प्राधिकार का मन्दाय लिए बिना ही, भारतीय जीवन की सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन कीमा के स्पष्ट में काफ़िर उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारीयों के लिए वे फारदे उन काफ़िरों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निःपेश मट्टदर वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उनका स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकूल है।

1312GI/85—7

अत. केन्द्रीय सरकार, उनका प्रधीनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे इसमें उपलब्ध अनुकूल में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहत हुए उनका स्थापन की नीति विषय के अवधि के लिए उनका ग्राहक के भर्ता उपवर्ती के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उनका स्थापन के मर्याद में नियोजक प्रादिविषय अधिकार निधि अनुकूल लिखानों को ऐसी विवरणिया भेजना और ऐसे लिखानों का निर्गमन के लिए ऐसी मुखियाएं प्रदान करेया जो केन्द्रीय सरकार, समय-मध्य पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक एसे नियंत्रण प्रधारा का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिन के भावाव मत्त्वात् करेया जा केन्द्रीय सरकार, उनका प्रधीनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के घट (क) के अधीन समय-मध्य पर निर्दिष्ट करें।

3. मामूलिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखांतों का विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, वीमा प्रार्थियम का भव्याव, लेखांतों का विवरण, विवरण प्रमाणों मत्त्वात् शादि भी है, जो उन थाले मध्य वीमाओं का बढ़त नियोजक बाटा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार दाग अनुसारित वीमा स्कीम के विवरण वीक पति, और जब कर्मा उनमें अनुसारन किया जाए, तब उन मंशाधन वीक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंदिया की आपा में उपकी मूल्य बीमों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेंगे।

5. विदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि के या उनका प्रधीनियम के अधीन छूट प्राप्त किया गया प्रधारन की भविष्य निधि का पहले ही मूल्य है उसके स्थापन व नियोजक किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक वीमा स्कीम के गदग्ग के रूप में उपका नाम तुरन्त इस विवरण दोर उपका बाबत आवश्यक प्रार्थियम भारतीय जीवन वीमा नियम के सन्दर्भ करेगा।

6. विदि उनका स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फारदे बढ़ाए, जाने हैं तो, नियोजक मामूलिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फारदों में भवित्वत रूप में बढ़ि के जो वीमा व्यवस्था करेया जिसमें कि उपकारियों के लिए गमिष्य ग्रामा स्कीम के अधीन उगलाउ फारदे उन काफ़िरों में प्रतिक अनुकूल हैं जो उनका स्कीम के अधीन अनुश्रूत है।

7. मामूलिक वीमा स्कीम में किसी बात के दौरान हुए भी, पर्दि जिसी कम्पनी के मूल्य पर इस वीमा के प्रधारन भवेय रूपमें उम रूपमें ये कम है जो भवित्वत वीमा को उम दशा में भवेय होता, जब वह उनका स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वार्त्ता/तामनिर्देशों को प्रतिक्रिया के रूप में दाना रकमों के प्रत्येक के बगवार रूपमें वीमा की मत्त्वात् करेगा।

8. मामूलिक वीमा स्कीम के उपवर्ती भी कार्ड भी नमाधन प्रार्थियम अधिकार निधि आपूर्ति वीर्याणा के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जो इस संग्रहालय गे कर्मचारियों के हित पर प्रतिक्रिया प्राप्ति गठन का विवाहत हो बहार, प्रार्थियम भविष्य निधि आपूर्ति, अपना अनुमति दाने में एवं उपकारियों का अपना दिविशाल ग्रहन की अनुश्रूत अवलम्बन करेगा।

9. पर्दि जिसे कार्णवल, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वीमा नियम को उम मामूलिक वीमा स्कीम के लिए, स्थापन पहले प्रस्ता भाना है, पर्दान नहीं रह जाने हैं, परं इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को पार्ट दाने वाले काफ़िर किसी गीति से कम हो जाने हैं तो यह छूट रुद की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणबाट, नियोजक प्रास्तीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियन्त तारंख के भीतर प्राप्तियम का गन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिम को उपयोग हो जाने प्रिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्राप्तियम के गन्दाय में किए गए किसी अधिकारम को बाहा में, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियाँ या विधिक नामियों को जो यत्र यह, छूट न दी गई होत, तो उक्त स्वाक्षर के अन्तर्गत होते हैं। बीमा फायदों के संशोधन का उत्तराधिकार नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधिन ग्राने वाले विनां सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, अंग्रेजी राशि के फ़ैक्टदार नामिर्विश्वासी/विधिक आर्थियों को उस राशि का सदस्य तत्पत्ता से और प्रत्यक्ष इशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे का प्राप्ति के एक साम के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मुद्रा एम-35014/305/सन-पर-1]

S.O. 119.—Whereas Messrs. Usha Electronics India (Private) Limited, Plot No. 222, Sector-25, Faridabad (PN/4885) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(305)/85-SS.JV]

का आ 120.—प्रेसर्स ग्राहीय इष्टनदेशादाल मिल लिमिटेड, फ़ैक्ट्रिया जीवन नथा नड़ दिला मे स्थित इष्ट आफिस महिन जनगांव, अस्ता द्वारा अवासीर मे स्थित कागदात अवमदावाद, अपार, फ़ाक्तुर, घासां भार नागपूर स्थित सेन्स आफिस (पा.यू./16) (जिस इष्ट द्वारा प्रभार उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी विधि और प्राप्त उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) जिस अंतर्गत प्रभार उक्त प्रविनियम कहा गया है) की धारा 17 की अवाग (2क) के अधिन छूट दिया कि विनां नियम हो।

आर केंद्रीय मरकार को नमाखान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी भूषक अधिकार या प्रोप्रियम का संशोधन किए जिन ही भारतीय जीवन बीमा नियम के नामहीक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के भूष में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये नामहीक उक्त फायदों ने आधिक प्रभुकृत है, जो कर्मचारी नियम प्रबन्ध को 1952 ए.स. 1970 (जिस द्वारा प्रभार उक्त नकोम कहा गया है) के अवाग उक्त अधिनियम है।

अत केंद्रीय नरकार, उक्त प्रविनियम की धारा 17 की अधार (2क) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनुदूता मे विनियोग जीवन के अधीन रखते हुए उक्त स्थापन को तोन वर्ष को व्यवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रबन्धन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीकण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केवल सरकार, समय-समय पर निश्चित करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीकण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर तन्दाय करेगा जो केवल सरकार, उक्त अधिनियम की वाय 17 की उपाधार (3क), के बाण (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीकण प्रभारी का सन्दाय आदि भी है, होने वाले अभी व्यर्थों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केवल सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की व्युत्संधा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवात, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अधिक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सम्पन्न करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कापदे देता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कापदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कापदे उन कापदों में अधिक प्राकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुरोग हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वार्ष में मन्देय होती, यदि यह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नामनिर्भेदिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बावजूद का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं, किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की की संभावना ही वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना थूटिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवधार देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना करा है, प्रदोन्ह नहीं रख जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले कापदे नियमी रूपनि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में प्रसक्त रहता है, तो पालिमी को व्यवस्था ही जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के नदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन पूर्व सदस्यों के नामनिर्देशियों पर विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई हानी तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कापदों के गन्दाय का उत्तराधिक्य नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन प्राप्त वाले किसी लदस्य को, छूट होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमा छूट राशि के लदस्य तापनिर्देशिती/विविध वारिसों को उम राशि तापनिर्देशित में प्राप्त प्रत्येक दशा में दूर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर भुनिर्देशित करेगा।

[मंज्ञा नं-35014/304/85-पर. पर. -4]

S.O. 120.—Whereas Messrs Jagjit Cotton Textile Mills Limited, Phagwara, District, Jullandhar including Head Office at New Delhi, Factories at Jagraon, Khanna and Abohar and Sales Office at Ahmedabad, Jaipur, Kanpur, Madras and Nagpur (PU/16) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available

able under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assured benefits to the provider or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/308/85-SS.IV]

काम आ। १२। — ऐसा दि तुरं लोकोंसामन थाक इण्डिया लिमिटेड,
१. वैष्णवीर लालिंग, भट्टाचार्य जी, डॉक्टर, १५३८ दो बोडे नं.
इल्लू. ग्रा. ११४४६२ में १८८८ (दिल्ली इण्डिया लिमिटेड सदत
स्थापन अद्य अहम है) दे १५३८ अंकित लिखि गया अन्तर्गत एवं व्यापक
भवित्वाता, १९३२ (१९३२ दि १२) (दिल्ली इण्डिया एण्ड ट्रेस्ट
प्रतिनिधि कार्य कार्य है) का जारी । १५३८ पर्वत (२३) के अधीन
छठ दिन दोनों दिल्ली लोकोंसामन दि ७ है,

आप येट्रीय स्टार के नामांकन की तरफ हैं जिस उत्तर-स्थान के कर्वीवंश से, जिसे गुरुदास सिंह द्वारा प्रभावित कर गया था। इस तिथि ही, मार्गशीर्ष तोला त्रिपुष्य पूर्णिमा ने भूमिका देकर सर्वात्म के अधीन जीवन बास्तव के लकड़े पर फैलाए उठा रखे हैं और ऐसे कर्मवरियों के लिए ये फायदे उन फारदों ऐ मधिम शत्रुकृत हैं, जो उत्तरांगी तिभ्रेष सहित बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इयोके पश्चात नवत शक्ति स्कीम कहा जाता है) के प्रबोन उठने वाले हैं;

अन् केन्द्रीय भरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उधारा (२६) प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हासि उपचार चनूली में विनिर्दित जनों के अवैन रहते हुए उक्त स्थान को तीन अर्पण की प्रथिक के लिए उक्त स्थीम के सभी उपर्याँ के प्रवर्तन से छूट देती है।

ਪੰਜਾਬ

१ उन स्थान के परिवेश में जितेह यादेशिक भविष्य निविदा
यादुकर्म फैशनम बंदूत को ऐसी दिव्यगिरा प्रेतेता और ऐसे लेपा गृहोत्ता
स्थान निर्गमन के दिन ऐसी नृविश्रां प्रदान करें जो केवल सज्जार,
समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मार्ग की समाप्ति के 15 फूट के भीतर सन्दर्भ करेगा जो केन्द्रीय भूगतर, उक्त अधिनियम की धारा 17 की आधार (अ) के वर्णन (या) के अंतर भवन-पार पर निर्दिष्ट करें।

३. यह दृष्टिकोण स्फीता रूपरेखा में, जिसके क्रमानुसार १, १०८ का सज्जा जनन, विवरणियों का प्रयुक्ति हित आता, जीवन प्रीतियम् का सद्व्याय, निवाप्रो का अन्तरग, निरंतरभग प्रमार्थों का सम्बन्ध इत्येति भी है, हमें बाले शमी आयों का बहुत निरन्तरक दृश्य हिता जगाएँ।

4 नियोजन, केन्द्रीय संसद द्वारा अनुमोदित बांग स्थीम के नियमों की एक प्रति, और जल कर्ता उनमें गोपनीयता दिया गया, ताकि यह संशोधन की प्रति तथा कानूनियों की व्यवस्था की शारीर में उपकार मरुष वार्तों का धनवाद, स्थापा के द्वारा नियन्त्रण करें।

5. यदि कोई ऐसा सम्बंधी, जो कल्पने विभिन्न विधि का या उक्त अधिनियम के अधीन यह प्रत्येक विधिवाल को प्रतिक्रिया का पहले ही सरका है, तो उस स्थिति में नियंत्रिति, यिर जाता है तो, नियंत्रण, सूहित विधि संघर्ष के सरकर के रूप में उत्तर नाम दुर्लभ है। इसके नाम से और उसकी बाबा अपकर्ता श्रीमित्र द्वारा योग्य विधि नियम को सम्बन्धित करेगा।

६ यदि उक्त स्थीय हरधनों का अपवाह करने वाले यहाँ प्राप्त जाते हैं तो, नियोक्त संग्रहित रूप से स्कॉल के अधीन कर्त्तव्यों का उपलब्ध फायदे में सम्भव। इसे युद्ध को जीतने का व्यवस्था करना चिरबो कि कर्त्तव्यों के लिए उपलब्ध रूप से स्कॉल के अधीन उपलब्ध फायदे उन कर्त्तव्यों से पर्याप्त अनुकूल हों, जो व्यापक स्कॉल व्यवस्था का नियंत्रण हैं।

७. सामुद्रिक बीमा। सरकार में किसी सात के होते हुए भी, यदि निर्णी कर्मचारी की मृत्यु पर इन स्कॉप के अधीन सन्देश रखा जाए तब से कम है जो कर्मचारी को उस दण्ड वे सन्देश होंगे, जब तक उनके स्कॉप के अधीन होता हो; तो, निर्णीकरण के लिए विधिवत् विधियाँ/उपलब्धिवित्तांको प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तों हैं अन्दर के बराबर रकम का सन्देश करेगा।

४. सामूहिक वीमा स्थानों के उपयोगी व कर्तव्य भी लेशोधन, प्रार्थिताक
भविष्य निधि अथवा परिवर्तन तंत्रालय के पुर्व अनुदेवन के द्वितीय गहना
किया जाएगा और जहाँ दिये गयों अल्पालय से लांचिंगों के हित पर प्रतिकूल
प्रभाव पड़ने की संभवता हो वहाँ, प्रेसिडिक भविष्य निधि अथवा,
अपना प्रतिपोषन देने से पूर्व कांचिर्यों को छपने दृष्टिवेण राष्ट्र दर्शन
का यथिवाक्तव्य भवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थान के फैसला, भारतीय दीदन वीषा नियम को उस समूहिक वैभाग संघर्ष के, जिसे स्थान पहले अपना चुका है, अद्वेन नहीं रह जाते हैं, तो इस रकीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फालते किसा रीति में काम हो पाते हैं, तो महालट रह की जा सकती है।

११. यदि किसी काण्डवश, निर्वाचक मारीच जीवन शीमा नियम द्वारा नियत तरीख के भीतर प्रीमियम का संदर्भ करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यापात हो आने विया जाता है तो सूद यह को जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन धृति सदस्यों के लाभान्देशितिपों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छुट न दो पहुँचते तो उक्त स्थिर के अन्तर्गत होते, बीमा फाईदों के सन्दर्भ का उत्तराधिक्षय नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के पश्चात धने थाले किसी मददा की सूत्र होने पर भागीय जीवन वीगा निगम, बीमालृत राशि के हृदय, नानदनिवेशिती, विद्यिक वारिसों को उस राशि का मंदाय तप्पणी से और प्रयोक वापस में हुर प्रकार से पूर्ण धबे की प्राप्ति वे एक भास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/307/85-एस.एस.-4]

S.O. 121.—Whereas Messrs. The Jute Corporation of India Limited, 1, Shakespeare Scrani, Calcutta and its branches covered under Case No. WB/14467, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Benefit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(307)/85-SS. IV]

का.वा. 137, १—शिरो प्रोफेशनल लिमिटेड, स्पेशल पॉइंटक्रूज थार्स, पोखर्वडा-360575 (जो.जे./3) (जिसे इसके पात्र तथा उस स्थापन का गया है) ने अमंगारी भविष्य और प्रकार्य उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की आ (17 की) उपचारा (2क) के अधीन इस जारी के लिए उन्नेस दिया है;

आई केन्द्रीय सरकार का समझान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिन्हीं के बीच अधिकार वा अधिकार वा मन्त्रालय दिया गया है, भारतीय जीवन वीवा नियम के अधीन जीवन वीवा के रूप में फारदे तथा ऐंड ऑर्टें एंटरप्रायरिस के लिए ये कायदे उन कायदों के प्रतिक प्रत्यक्ष हैं, जो कर्मचारी नियम सहमद्वय वीवा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेष्य हैं;

प्रति केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविधियाँ की धारा 17 की उपचारा (2क) का तात्पर्य अधिकारी वा प्रत्येक व्यक्ति और उसके उपचार अनुशृण्णी में विविध रूपों का अधिकार उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थीम के अधीन उत्तर्वा के प्रवर्तन से कट देती है।

अनुशृण्णा

1. उक्त स्थापन के अनुशृण्णी में विविध प्रादर्शिक भविष्य नियम आयुक्त गुरुभात की देसी विवरणियाँ देजेगा और ऐसे हेतु रखेगा तथा नियोजन के लिए ऐसी विवाह प्रदान देनेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजन, ऐसे विवरण प्रादर्शिक वीवा की नियमित के 15 दिन के भीतर सम्बाद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविधियाँ की धारा 17 की उपचारा (2क) के लिए (क) के अधीन तात्पर्य समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. समूहिक वीवा स्कीम के प्रगाम में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणियाँ का प्रस्तुत किया जाना, वीवा प्रीमियम का संशोधन, लेखाओं का अन्तर्गत विवरण प्रादर्शिक सम्बाद आदि भी है, इने वाले सभी व्यक्ति का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वीवा स्कीम के नियमी की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस प्रादर्शित की प्रति तथा कोर्टायियों की वक्तुंगवारी की भाषा में उसकी मुश्त वालों का प्रत्यावर्त, न्याय के सूत्रान्तर्क पर उत्तरित करेगा।

5. यदि कार्ड एवं वीवा कर्दवारी, जो कर्मचारी भविष्य नियम का उक्त अधिनियम के अधीन लूट प्राप्त किया स्थापन की भविष्य नियम हो, एवं उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो, नियोजन, समूहिक वीवा स्कीम के संशोधन के रूप में उसका तात्पर उत्तर वर्ज करेगा और उनकी वाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन वीवा नियम का सन्दर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बहाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में व्युत्तर रूप से दृढ़ी जाने की व्यवस्था नहीं जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन असूये हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विशिष्ट वारिस/नामनिर्णिती की प्रतिक्रिया के रूप में दोनों ग्रन्ती के ग्रन्तीर के बिचारण रकम का सम्बाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक विविध नियंत्रण आयुक्त प्रावित के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो चर्चा, प्रावेशिक विविध नियंत्रण आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तियुक्त प्रवर्तन देगा।

9. यदि किसी राजावाच, व्यापार के कर्मचारी, मार्गीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पत्र से अपना दूका है, अधीन नहीं रख जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे फिरी गीति से कम हो जाने हैं, तो यह रक्त रक्त की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संबाय करने में घसफर रहता है, तो पारिसी को व्यापार हो जाने दिया जाता है तो छट रक्त की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदर्भ में किए गए किसी व्यक्तिका की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विशिष्ट वारिसों की जो यदि यह, लृट स दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले कायदों का मन्दाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाकृत गणि के हक्कावार नामनिर्देशितियों विशिष्ट वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रयोक दशा में तंत्र प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/306/85-प्रम.एम.-4]

S.O. 122.—Whereas Messrs. The Associated Cement Company Limited, Special Products Works, Porbander-360574 (GJ) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(306)/85-SS. IV]

नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 1985

का. आ. 123.—कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा 1 जनवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उस प्रधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के मिलाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के मिलाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपर्युक्त राज्य के "हुलकोटी" केन्द्र के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	झोल्ली	तालुक	जिला
1.	हुलकोटी	गडग	गडग	धारवाड
2.	टाउन प्लानिंग कमेटी (टी.पी.सी.) बीमा	गडग	गडग	धारवाड
3.	श्रीनकाशकटी	गडग	गडग	धारवाड
4.	गु.पी.सी. बीमा विनकाशकटी	गडग	गडग	धारवाड

[सं. एम-38013/20/85-एम. एम-1]

New Delhi, the 20th December, 1985

S. O. 123. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st January, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas of "Hulkoti" Centre in the State of Karnataka, namely:-

Sl. Revenue Villages No.	Hobli	Taluk	District
1. Hulkoti	Gadag	Gadag	Dharwar
2. Town Planning Committee (PTC) Limit.	Gadag	Gadag	Dharwar
3. Binkadakatti	Gadag	Gadak	Dharwar
4. U.P.C. Limit Binkadakatti	Gadag	Gadag	Dharwar

[No. S-38013/20/85-SS-I]

का. आ. 124.—कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा 1 जनवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उस प्रधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के मिलाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के मिलाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपर्युक्त कर्ताक राज्य के "बेलवाडी" केन्द्र के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	झोल्ली	तालुक	जिला
1.	बेलवाडी	हलावाला	मैसूर	मैसूर
2.	होटागली	मैसूर	मैसूर	मैसूर
3.	कूर्हाहानी	हलावाला	मैसूर	मैसूर
4.	हलावाला	हलावाला	मैसूर	मैसूर
5.	हेब्बल	मैसूर	मैसूर	मैसूर

[संक्ष. एम-38013/21/85-एम. एम-1]

ए.० कॉ. भट्टराई, अवर सचिव

S.O.124.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st January, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas of "Belwadi" Centre in the State of Karnataka , namely:-

Sl. Revenue Villages No.	Hobli	Taluk	District
1. Belwadi	Elawala	Mysore	Mysore
2. Hotagally		Mysore	Mysore
3. Koorgahally	Elawala	Mysore	Mysore
4. Elawala	Elawala	Mysore	Mysore
5. Hebbal	Mysore	Mysore	Kasaba

[N. S-38013/21/85-SS-I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy|

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 1985

का. आ. 125.—श्रीद्वयिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुमति में, केंद्रीय सरकार, भारत को विग्रह कोन लि. की इस मुग्नदीह कोशियरी के प्रबंधतांत्र से संबद्ध नियोजनों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुरूप में निश्चिप श्रीद्वयिक विवाद में केंद्रीय सरकार, श्रीद्वयिक अधिकारण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करनी है, जो केंद्रीय सरकार को 18-12-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 24th December, 1985

S.O. 125.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Bhuggatdi Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th December, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 83 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Bhuggatdih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. P. Singh, General Secretary, Khan Mazdoor Congress.

On behalf of the employer—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE I Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 10th December, 1985

AWARD

The Government of India Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(35)/85-D. III(A), dated, the 29th May, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Bhuggatdih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Ltd., in dismissing from service Shri Parmeshwar Singh, Dumper Driver, with effect from 7-9-1984 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Parmeshwar Singh was working as a permanent Dumper Driver from 12-6-81 at East Bhuggatdih Colliery of M/s. B. C. C. Ltd. On 7-7-84 the concerned workman was on duty in the third shift from 12 midnight to 8.00 A.M. on 8-8-84. On that day he was deputed to transport coal on dumper No. BHG 8652 from No. 6 Pit to No. 3 depot. The road from No. 6 Pit to No. 3 depot is kuchha and full of pit holes. Due to heavy rainfall depot No. 3 was covered with knee deep water and as such the transporting of coal from No. 6 Pit to No. 3 depot was a dangerous exercise for the Dumper Driver. While the concerned workman was transporting coal on the Dumper at 6.30 A.M., it fell inside the pit hole in the depot while the concerned workman could not locate due to the water logging on the surface. As a result of dumper falling in the pit hole it went out of order and it was damaged. The concerned workman informed the colliery Engineer over telephone, regarding the incident whereupon the colliery engineer advised him to complete the work on another dumper. Accordingly the concerned workman took another dumper from the workshop and completed the job till 8 A.M. On 10th July, 1984 the management chargesheeted the concerned workman and suspended him pending enquiry alleging him that he had intentionally damaged the dumper. On 11-7-84 the concerned workman replied to the chargesheet denying the allegation. The management fixed the date of domestic enquiry on 28-7-84 through their office letter dated 25-7-84. The concerned workman presented himself in the enquiry. As the management's witness did not turn up and as such the concerned workman left the place. He was again informed of the next date fixed in the enquiry. After holding the enquiry, the management dismissed the concerned workman through their office order dated 7-9-84. The union took up the case of the concerned workman with the management but no reply was sent by the management. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad and on failure of the conciliation the present reference was made.

According to the workmen the management had utterly failed to prove the malafide intention of the concerned workman. The concerned workman would not have risked his life by driving the dumper negligently only with a view to harm the management. The accident was not due to the negligence on the part of the concerned workman rather it was caused due to negligence on the part of the management in maintaining the depot and the Kuchha Road. It is prayed that the concerned workman be reinstated on his original job with full back wages.

The case of the management is that the concerned workman was dismissed from service on proved misconduct established in a departmental enquiry held into the chargesheet issued against him. In course of driving the dumper at No. 3 Pit depot the concerned workman positioned the dumper on an undulating ground with the left side rear wheel in a ditch of 2-1/2 feet deep and thereafter operated hydraulically operated telescopic cylinder with a view to unload the coal into the dumper into depot at No. 3 pit causing weight of the coal shifted to the left side and due to unable action the hydraulic jack got broken and the chassis of the dumper cracked on the right side. Although there was enough space of even ground for properly driving and positioning the dumper on a level ground, the concerned workman either intentionally or recklessly operated the hydraulic unloading devise by placing the dumper on a tilted dumper putting the left rear wheel about 2 feet below the ground level and caused severe damage to the costly heavy vehicle. After making necessary investigation of the dumper the place of occurrence, the damage caused to the dumper and obtaining opinion from the experts it was conclusively established that the concerned workman caused severe damage to the dumper either intentionally or recklessly without caring for the consequences. In order to conceal facts the concerned workman tried to misled the Executive Engineer by giving wrong information to him. The concerned workman was issued with a chargesheet dated 10-7-84 to which he submitted his reply by his letter dated 11-7-84 denying the allegation. He did not make specific denial or admission of the facts stated in the chargesheet relating to the severe damage caused to the dumper. The departmental enquiry was conducted by Shri R.P. Singh, Sr. P.O. of East Bhuggatdih Colliery in the presence of the concerned workman. The enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice. The concerned workman was given full opportunity to take the assistance of co-worker to cross-examine the management's witness and he was also given opportunity to produce his own defence witness in his defence. The concerned workman did not properly cooperate in the enquiry and sometimes took arrogant posture. The enquiry officer submitted his enquiry report dated 14-8-84 holding the concerned workman guilty of the charges of misconduct levelled against him. After considering all the materials the management decided to dismiss the concerned workman. A letter of dismissal was issued on 7-9-84 under the signature of the Agent of the Colliery after obtaining approval from higher authorities. The Agent of the Colliery is competent authority to dismiss the concerned workman under the Standing Orders.

Two question have been raised on behalf of the concerned workman. The first question is whether the concerned workman had intentionally or negligently caused damage to the dumper and whether the punishment of dismissal was called for even if it was an act of negligence on the part of the concerned workman.

A preliminary point had already been raised whether the enquiry was fair and proper and the said matter was decided by an order passed by this Tribunal on 8-10-85 holding that the enquiry was fair and proper. It is therefore to be seen on the materials before the Enquiry Officer in the domestic enquiry whether the charge was established against the concerned workman and whether the established charge called for the punishment of dismissal of the concerned workman from service. It is the admitted case of the parties that the concerned workman while on duty on the alleged date was driving the dumper in question and that it was damaged at No. 3 Pit depot. Ext. M-2 is the reply of the concerned workman to the chargesheet submitted against him which shows that the concerned workman had informed the Executive Engineer over telephone that the dumper on which he was working was damaged but he had not given the details as to how the damage was caused. Ext. M-6 is the complaint made by Shri D. Singh, Engineer to the Superintendent, East Bhuggatdih Colliery dated 8-7-84. It states the parts of the dumper which were damaged. It is stated that after a minute inspection it was observed that the tipper was damaged intentionally as there was an ample place for the dumper to tip coal at the depot but he drives with a bad intention took the loaded dumper into the muddy ditch which caused the above break down. It is clear from this report that the dumper was damaged as it was driven in the muddy ditch. Admittedly no witness had seen the occurrence

The witnesses have just drawn their conclusion regarding the intention on the basis of the nature of damage caused to the dumper. The evidence of the witnesses namely Shri K. Mangapatty and Shri Devendra Singh Engineers does not show that the concerned workman was driving the dumper with an intention to cause damage to the dumper. The photograph marked Ext. A-1 to A-7 shows the different position of the damaged dumper and the same cannot be used to establish that damage was caused due to the negligence or illmotive on the part of the concerned workman. On consideration of the entire material I am of the opinion that the management has not been able to establish that the concerned workman had damaged the dumper with an intention to cause its damage.

It will appear from teh chargesheet that the Dumper was driven in a muddy ditch. It is submitted on behalf of the concerned workman that as the ditch was muddy it was not possible for him to assess the depth of the ditch and as such he had driven the dumper through the ditch which resulted in the tilting of the dumper. It is true that it is difficult to assess the depth of a ditch when it is muddy and as such the concerned workman drove the dumper through the ditch without knowing that the dumper will be packed in the ditch. So far driving of the dumper through the ditch is concerned, I do not think that there was much of negligence on the part of the concerned workman. It appears that after the dumper was packed in the ditch the concerned workman operated the hydraulically operated telescope cylinder with a view to unload the coal from the dumper into depot at No. 3 Pit. The concerned workman caught to have realised that the weight of the coal lifted to the left side by the telescopic cylinder would cause unbalance causing further damage to the parts of the dumper. This may not be intentioned on the part of the concerned workman but certainly it is an act of negligence and carelessness on his part and he should not have unloaded the coal after the dumper was packed in the ditch. It was surely an error of judgement on the part of the concerned workman and it was expected of him that he would not have operated the telescopic cylinder for unloading the coal in that position. I hold therefore that there was some negligence or act of misjudgement on the part of the concerned workman in operating the unloading machinery of the dumper in titled position of the dumper in the ditch but at the same time I must say that the management has no evidence to show that the concerned workman had any intention in causing the said incident. In view of the above the punishment of dismissal inflicted upon the concerned workman appear to be too severe for the act of his misjudgement and negligence. Accordingly I am of the view that the punishment of dismissal imposed upon the concerned workman is too severe and requires modification.

The concerned workman was under suspension from 10th of July, 1984, and was dismissed from service with effect from 7-9-84. In my opinion the concerned workman does not deserve the punishment of dismissal and he deserves to be reinstated. The non-payment of part wages during the period of suspension and non payment of wages after the order of dismissal till his reinstatement will be enough punishment to meet the ends of justice.

In the result, I hold that the action of the management of the East Bhuggatdih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. in dismissing the concerned workman from services is not justified and the ends of justice will be met by reinstating the concerned workman within one month from the date of notification of this award but the concerned workman will not be paid any wages for the period after his dismissal from service or any amount excess of the subsistence allowance during the period of his suspension which in itself will be sufficient punishment for his negligence.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. 1-20/12/35/85-D. III (A)]
A.V.S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली 26 विसम्बर 1985

श. आ. 1.16.—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय अधिनियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित टेका (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रवल अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें विमलसिंह भद्रम्य शामिल होंगे, अर्थात्:—

1. श्रम मंत्रालय में राज्य भ्रमी	अध्यक्ष
2. मुख्य श्रमाधिकार (केन्द्रीय) नई दिल्ली	मवस्था पदेन
3. श्री भार. के. सुन्दरम्	केन्द्रीय सरकार
प्रमुख इंजीनियर (एफ. जैड) केन्द्रीय सोक नियमणि विभाग, प्रियंग श्रीरामाचाम मंत्रालय, नई दिल्ली	केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
4. श्री तीर्थ प्रकाश, निदेशक, सिविल इंजीनियर रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली	रेल मंत्रालय का का प्रतिनिधित्व करने वाले

श्रृंखला

श्री एस. एस. राणा निदेशक, यातायात-वाणिज्य (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली	रेल मंत्रालय का भार निदेशक, प्रशासन, (एस.) रेल मंत्रालय, (रेलवे प्रतिनिधित्व करने बोर्ड) नई दिल्ली
5. श्री पी. एच. तालाल,	रेल मंत्रालय का

भार निदेशक, प्रशासन, (एस.) रेल मंत्रालय, (रेलवे प्रतिनिधित्व करने
बोर्ड) नई दिल्ली

विकल्प :

श्री एन. पद्मनाभन, भार निदेशक, प्रशासन, (एन.) रेलवे बोर्ड	कोयला खानों के नियोजकों का प्रति- निधित्व करने वाले
7. श्री प. बालिका, मुख्य कार्मिक प्रबंधक गार्डीय अनियंज विकास नियम नियमित्त,	कोयला खानों के भिन्न खानों के नियोजकों का प्रति- निधित्व करने वाले
10-3-311/ए, केस्ट हिल्मा, मसाव टैक, हिंदोबाब-505028।	—पथोक्त—
8. श्रीएम. एल. गाराबानी, अध्यक्ष, केइरेशन आंक हाईयन मिनरल हाईस्ट्रीज, मैमर्स एस. के. माराबानी एंड कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, रायचूट विल्डिंग, पट्टनी मंजिल 25-12-36, गोदावरी स्ट्रीट, विशाखापत्तनम- 530501 (आंध्र प्रदेश)	टेकेदारों का प्रति- निधित्व करने वाले

9. श्रीटी. एन. सुभाराम, अध्यक्ष
मैमर्स विल्डर्स एसोसिएशन आंक हाईयन, आंक प्रबंध नियित्व करने वाले
निदेशक, मैमर्स गमन हाईयन लिमिटेड जी-1/जी-20,
कामसू मेंटर, गान्धी नगर, नारदेश, बम्बई-4000
34

विकल्प : वाराध्यम, मैमर्स विल्डर्स जी-1/जी-20, कामसू
सेटर, गान्धी मंजिल, नारदेश बम्बई-400034

10. श्रीहजारी नायम भगवान्न,
अध्यक्ष
टि सेक्टर विल्डर्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), दिल्ली-
14/1, रामल विल्डिंग, रामल एस.सी.ई. दिल्ली-1

11. श्री वी. सी. घोष, वर्सिठ एडवोकेट, प्रेसीडेंट, उच्चतम न्यायालय तथा प.न. एफ. रेलवे कर्मचारियों करने वाले	रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	4. Shri Tirath Parkash, Director, Civil Engineering, Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.	Representing the Railways
12. श्री सौ. शशिभूषण राय, महामंत्रिव, एस. ई. रेलवे मैन कंप्रेस, रेलवे इनाक भ. - 112/6, यूनिट-2, मानव इंस्टीट्यूट रेलवे कार्यालयी गाडीन रीच, कलकत्ता-43।	रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	Alternative; Shri S.S. Rana, Director, Traffic Commercial, Railway Board.	
13. श्री प.स. बासुगुप्ता, महामंत्री, हैंडिगम, नेशनल माइन वर्कर्स फैडरेशन, राजेंद्र पथ, प्रतिनिधित्व करने वाले धनबाद-826501।	कोयला खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	5. Shri H.P. Tayal, Additional Director Estt(S), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.	Representing the Railways
14. श्री बी. चौधरी, महामंत्री, हैंडिगम नेशनल ट्रेड यूनियन कंप्रेस, राजस्थान शाखा, काकी हाउस, पम. प्राइ. गोड, जयपुर-302001।	कोयला खानों से भिन्न खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	Alternative; Shri N. Padmanabhan, Additional Director Establishment(N), Railway Board.	
15. श्री प्रियंश चंदा, महामंत्री, द्रेड यूनियन कंप्रेस (लेनिन चारणी) तथा प्रेजीडेट, कापर मजदूर यूनियन, 4/11772, सतनगर, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 वाले।	कोयला खानों से भिन्न खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	6. Shri A.V. Brahma, Chief of Personnel, Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.	Representing the employees in Coal Mines
16. श्री लक्ष्मण रघुवंश तिहु, भारतीय मजदूर संघ, म्यूमिलिपल क्वार्टर्स, परेश गांडीज, जम्मू-180001	ठेकेदारों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	7. Shri A. Khalique, Chief Personnel Manager, National Mineral Development Corporation Ltd., 10-3-311/A, Castle hills, Masab Tank, Hyderabad-500028.	Representing employers in mines other than coal mines.
17. श्री पी. प्रार. मुभायास्मदन, अध्यक्ष, फैडरेशन आफ्रिकाल हैंडिगम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, मार्फेन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, डी. औ. एन. पी. ब्लॉक, डाकघर नेबल ब्रेस, विशाखापत्तनम-530014, आंध्र प्रदेश।	अधिकारी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	8. Shri M.L. Sirawagi, President, Federation of Indian Mineral Industries, M/s S.K. Sirawagi & Co. (P) Ltd., "Rochlitt Building", 1st Flr, 25-32-36, Godeyvar Street, Visakhapatnam-530001(AP) Alternate Shri R.K. Sharma, Secretary, Federation of Indian Mineral Industries, 301, Bakshi House, 40-41, Nehru Place, New Delhi-110019.	Representing employers in mines other than coal mines.
अम मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव केन्द्रीय टेका अधिक सलाहकार बोर्ड के सचिव होंगे।	[सं. एस/16025/9/84/एल. इस्यू.]	9. Shri T.N. Subba Rao, President, M/s Builders Association of India, and Managing Director of M/s Gammon India Ltd., G-1/G-20, Commerce Centre, 5th Floor, TARDEO, Bombay-400034.	Representing Contractors.
New Delhi, the 26th December, 1985	ए. के. श्रीबास्तव, महामंत्री	Alternate Vice-President, M/s. Builders Association of India G-1/G-20, Commerce Centre, 5th Floor, Tardeo, Bombay-400034.	
S.O.126. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970(37 of 1970) read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby reconstitutes the Central Advisory Contract Labour Board, consisting of the following members, namely:-	अम कल्याण/भारत सरकार के संयुक्त सचिव		
1. Ministry of State in the Ministry of Labour CHAIRMAN			
2. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi. Ex-officio Member			
3. Shri R.K. Sundaram, Chief Engineer(FZ), Central Public Works Department, Ministry of Works and Housing, New Delhi. Member representing the Central Govt.			

10. Shri Hazuri Lal Marwah, President, The Central Builders Association (Regd). Delhi, 44/1, Regal, Building, Connaught Place, New Delhi-110001.	Representing Contractors
11. Shri B.C. Ghose, Senior Advocate, Supreme Court of India and President, N.F. Railway Mazdoor Union, All India Railwaymen's Federation, Rama Krishna Avenue, Patna-800004.	Representing employees in Railways
12. Shri Ch. Seshibhushana Rao, General Secretary, S.E. Railwaymen's Congress, Railway Block No. 112/6, Unit 2, South Eastern Railway Colony, Garden Reach, Calcutta-700043.	Representing employees in Railways
13. Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers Federation, Rajendra Path, Dhanbad-826001.	Representing employees in Coal mines.
14. Shri B. Chaudhury, General Secretary, Indian National Trade Union Congress Rajasthan Branch, Coffee House, MI Road, Jaipur-302001.	Representing employees in mines other than coal mines
15. Shri Pritish Chanda, General Secretary, United Trade Union Congress (Lenin Sarani), and President, Copper Mazdoor Union, 4/11772, Sat Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.	Representing employees in mines other than coal mines.
16. Shri Lakshman Ravinder Singh, Bhartiya Mazdoor Singh, Municipal Quarters, Parade Ground Jammu-180001.	Representing Contractors employees
17. Shri P.R. Subaschandran, President, Federation of All India Hindustan Construction Workers' Union, C/O Hindustan Construction Co. Ltd. DGNP Area, P.O. Naval Base, Visakhapatnam-530014 (A.P.).	Representing Contractors employees

Deputy Secretary, Ministry of Labour, New Delhi will be the Secretary of the Central Advisory Contract Labour Board.

[No. S-16025/9/84/LW]
A.K. SRIVASTAVA, Director General
(Labour Welfare) Lt. Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1985

का. आ. 127.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर
ति सोकल्ति में ऐसा करना अपेक्षित था श्रीदेविक विवाद अधिनियम,
1947 (1947 वा 14) नी भारा 2 के खंड (d) के उपखंड (VI) के
उपर्युक्तों के अनुसरण में सामग्री सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना में

का. आ. 3067 दिनांक 12 जून, 1985 द्वारा बैंक नोट प्रेस डेवास को
लक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 5 जूलाई, 1985 से छ. मास की
को कालावधि के लिए लोक इप्पयोंसी सेवा गोपनीय था।

आरक्षेन्द्रीय सरकार की यथा है कि सोकल्ति में उक्त कालावधि का
छ. मास को और जनावरी के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

का. आ. 3067 दिनांक 12 जून, 1985 द्वारा बैंक नोट प्रेस डेवास को
लक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 5 जूलाई, 1985 से छ. मास की
को कालावधि के लिए लोक इप्पयोंसी सेवा गोपनीय करती है।

[एस० 11017/14/85-दी-1(ए)]

4. १२. मृ. अमर, अवृ. सचिव

New Delhi, the 26th December, 1985

S.O. 127.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 3067 dated the 12th June, 1985 the Bank Note Press, Dewas (MP) to be a public utility service for the period of six months, from the 15th July, 1985;

And Whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 15th January, 1986.

[No. S-11017/14/85-D.I(A)]
S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1985

का. आ. 128.—कूनापत्थर और डोलामाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973, के नियम 3 के माध्यम पठित कूनापत्थर और डोलामाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, धारा 2, खंड 3 उप खंड (ii), तारीख 19 मई, 1984 को पृष्ठ 1513 पर प्रकाशित अधिसूचना संभवा का, आ. 1676 तारीख 24 जून, 1983 में निम्न संशोधन करती है:

उत्तर प्रधिसूचना में, क्रमांक 1 की प्रतिचिह्नों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिचिह्न रखी जाएगी, अवृत्त:—

1. श्री नकुल पाटिल
2. श्रम राज्य मंत्री
- महाराष्ट्र

[पृ. 23015/15/80-एम-5/कल्याण-2]
रवि दत्त मिश्र, अवृ. सचिव

New Delhi, the 27th December, 1985

S.O. 128.—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) read with Rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby amends the Notification No.

S.O. 1676 dated the 24th June, 1983 published at page 1513 of the Gazette of India Part. II Section (3) Sub-Section (ii) dated, the 19th May, 1984 as under :

In the said notification, for-entries at serial number 1, the following shall be substituted namely :—

1. Shri Nakul Patil,

Minister of State for Labour
Maharashtra

[No. U-23015|15|80-MV/W.II]
R. D. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1985

का. प्रा. 129.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की घारा 8 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संस्थान के नाम को उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है, अर्थात् :—

“राष्ट्रीय अम संस्थान”

[सं. ए-45019/1/85-इन्डस्ट्रीज़ (एन.एल.आई.)]

New Delhi, the 27th December, 1985

S.O. 129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby add the name of the following institute in the Schedule to the said Act, namely :—

“National Labour Institute”

[No. A-45019/1/85-WE(NLI)]

का. प्रा. 130.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की 19) की घारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निवेदा रही है कि उक्त अधिनियम के उपबंध राष्ट्रीय अम संस्थान के कर्मकारियों के कायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि पर पहली जुलाई, 1974 से लागू होंगे।

[मंज्या ए-45019/1/85-इन्डस्ट्रीज़. ई. (एन. एल. आई.)]

चिना चौपड़ा, निरेशक

S.O. 130.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby direct that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the Employees of National Labour Institute with effect from the 1st July, 1974.

[No. A-45019/1/85-WE(NLI)]

SHITALA CHOPRA, Director

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1985

का. प्रा. 131.—आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दिवीजनल इंजीनियर, टेलीफ्राम, बिलासपुर (एम. पी.) के प्रबंध संत से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निश्चित आद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-12-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th December, 1985

S.O. 131.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, 724 Napier Town, Jabalpur, (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Engineer, Telegraph, Bilaspur (M.P.) and their workmen; which was received by the Central Government on the 18th December, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BQMBAY

Reference No. CGIT-2/19 of 1985

(Transferred to this Tribunal vide Ministry's order No. S/11025 (1)/85-D.IV(B) dated 8-2-1985 from Jabalpur)

PARTIES

Employers in Relation to the Management of Division
Engineer Telegraph, Bilaspur (M.P.)

AND

Their Workmen

APPEARANCES

For the Employers : Shri A. P. Tare,

Advocate

For the Workmen : Shri Arvind Srivastava,

Advocate

INDUSTRY : Posts and Telegraph

STATE : M.P.

Bombay, dated the 8th November, 1985

AWARD

By their order No. L-40012(10)|82-D.II(B), dated August, 1983 and the corrigendum dated 28-3-1984 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

“Whether the action of the Divisional Engineer, Telegraph Bilaspur Division, Bilaspur (M.P.) in terminating the services of S/|Shri Mani Ram Soni, Pandumanlal Soni and Krishnakumar Soni, workmen from 21st July, 1982 is justified? If not, to what relief these workmen are entitled to ?

2. The case of the workmen is that they were gainfully employed in the Air Conditioning plant at Bilaspur Exchange under the Posts and Telegraph Department. Shri Mani Ram Soni was appointed on 18-5-1980, Shri Pandumanlal Soni on 17-7-1980 and Shri Krishna Kumar Soni on 1-2-1981 in the Auto Telephone Exchange, Bilaspur which at that time was under the over-all control of Executive Engineer (Electrical) Bhopal. It is alleged that on 1-5-1982 the Divisional Engineer Telephone Bilaspur took over from the Executive Engineer (Electrical) Bhopal. However before that Shri Mani Ram was promoted to the position of an Operator and paid at rate of Rs. 9 per day while the remaining two helpers were being paid at Rs. 5.66 per day at which rate they continued till 30-4-1982. The department however reduced those wages to Rs. 5.50 per day without issuing any notice etc., with the result they had to approach the Assistant Labour Commissioner (Central) since all the request to redress the grievance fell on the deaf ears of Circle Engineer, Bilaspur. When the matter was pending with the ALC(C), Bilaspur suddenly with effect from 27-7-1982 the Sub-Divisional Officer, Bilaspur stopped these workmen from working and hence the dispute and the reference.

3. By their written statement the department contends that these three workmen were employed at the time of construction of the Air condition Plant, on completion of which work the service of the three workmen came to an end and they were never the employees of Divisional Engineer, Telephones, Bilaspur. It is further stated that the Industrial Disputes Act is not applicable. The management admits that the workmen were employed on daily wages from 18-5-1980, 1-7-1980 and 1-2-1981 respectively as contended but it is stated that this was at the time of construction work and it is also admitted that they were respectively serving as Operator and Helpers and it is alleged that on completion of the work their services came to an end and thereafter they started working as casual labour on daily wages of Rs. 5.50 per day. It is further contended that since the employment was for a limited purpose and no offer of appointment in writing was made no relief is permissible. Lastly it is urged that there is no post of Air Condition Plant Operator, and the opponent is not entitled to employ any person without passing any valid order by the competent authority on receipt of the sanction of the Director General of Posts and Telegraphs.

4. On the above pleadings the following issues arise for determination and my findings thereon are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the action of the Divisional Engineer, Telegraph, Bilaspur Division, Bilaspur in terminating the services of S/Shri Mani Ram Soni, Padumanlal Soni and Krishna Kumar Soni, workmen from 21st July, 1982 is justified ?	No
2. If not, relief and costs ?	As per award.

REASONS

5. In support of the contention of the workmen there is the evidence of Shri Mani Ram Soni who has reiterated the facts mentioned in the statement of claim and it is supported by three certificates Ex. W-1, W-2 and W-3 issued by the Junior Engineer, Posts and Telegraphs, Air Conditioning Section, New Auto Telephone Exchange, Bilaspur fully substantiating the case of three workmen. Further the certificates issued by the same officer in favour of Shri Mani Ram Soni, Shri Padumanlal Soni and Shri Krishna Kumar Soni respectively Operator and Helpers are showing that till March, 1982 each of them had put in more than 240 days of service. Now if it is the case as stated namely from 18-5-1980, 17-7-1980 and 1-2-1980 they were employed (in the case of Shri Padumanlal Soni the workmen say that he started working from 17-7-1980 while the department says that he started working from 1-7-1980) and if they were continuously in the service as stated by the witness and also proved by the certificate issued then unless there is written order that they were appointed for a limited period only from 1980 and 1981 respectively till the date of cause of action namely 27-7-1982, they having completed more than 240 days would be entitled to notice of termination and compensation under Section 25 F of the Industrial Disputes Act which the department has never done. The termination therefore is invalid and illegal and unjustified.

6. However, the contention of the management seems to be that they do not have the post of Operator. The evidence also shows that these workmen do not possess any technical diploma, that they were never employed through Employment Exchange. If therefore the department finds it difficult to continue them in service, against which as already seen they had a right to continue on account of their service for more than two years, and further we notice that the termination was not legal and valid, the first thing which we will have to follow is to declare the action as invalid and unjustifyed at the same time instead of reinstating them appropriate relief in the circumstances of the case shall be to award compensation. The first workman was getting Rs. 9 per day and the remaining two were getting Rs. 5.66 each per day as certified by the Junior Engineer, they shall be therefore entitled to back wages till the date of award at the same rate. However, instead of ordering reinstatement the department is directed to pay Rs. 22,000 by way of compensation to Shri Mani Ram Soni and Rs. 15,000 each to S/Shri Padumanlal Soni and Krishna Kumar Soni.

Award accordingly.

Dated : 15-11-1985.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-40012(10)/82-D.II(B)]

का. प्रा. 132.—औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रनमण में, केन्द्रीय सरकार सलाल शाहड़ो प्रोटेक्ट इमेजिनियर, अधितिप्रसंग के प्रबंधनकाल से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विकास में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 132.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Salal Hydro Electric Project, Jyotipuram Distt. Udhampur and their workmen which was received by the Central Government on the 16th December, 1985.

**BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 28 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Salal Hydro Electric Project,

AND

Their Workman : Bishan Singh

APPEARANCES :

For the Employers : Sh. J. N. Kochhar.

For the Workman : Sh. H. N. Biswas.

ACTIVITY : Salal Hydro Electric Project **STATE :** J&K

Dated, the 10th December, 1985

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. I-42012(5)/84-D, II(B) dated the 17th of July, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the termination of services of Shri Bishan Singh S/o. Sh. Lochan Singh Ex-Driver by the management of Salal Hydro Electric Project with effect from 26-2-80 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Brief facts of the case according to the petitioner are that he was employed as a Cleaner by the Resptd. Project w.e.f. 10-4-1973 and was promoted as Driver on 13-7-1978, that he continued serving them as such till 26-2-1980 when his services were abruptly terminated without any prior notice or payment of terminal benefits as envisaged under Section 25-F of the Act. It was averred that the management did not even charge sheet him for initiating the impugned action. He therefore, prayed for his reinstatement on quashing the termination and payment of full back wages.

3. Contesting the proceedings, the management propounded that even though the petitioner was employed with them from April 1973 till termination of his services and that no terminal benefits were given to him yet his disengagement was inescapable because of the peculiar situation created by him. It was alleged that the petitioner was a trouble shooter, alcoholic and a quarrelsome character who often indulged in riotous and disorderly behaviour with his colleagues and others working at the Project for auxiliary services. It was pleaded that in July, August and September 1979 the petitioner had picked up quarrel with some hotel-owners and beat up their staff resulting in registration of criminal cases against him by the policies. Moreover he was a habitual absentee who paid no heed to their repeated reprimands and to crown it all, on 19-2-1980 under the influence of liquor he intruded into the residential quarter of one of their Electrician Mohinder Singh and at the point of dagger forced him to arrange the supply of electricity to a residential quarter which had been unauthorisedly occupied by his (petitioner's) friends. The incident created great unrest at the Project and a large number of employees including those covered by major Labour Unions struck work and shouted agitated slogans which left no other course with the Management except to discharge him summarily. All the same one month's salary in lieu of notice was offered to him.

4. In support of their respective versions both the parties filed the relevant documents and opted against leading any oral evidence for the simple reason that the facts were not in dispute.

5. On a careful scrutiny of the entire available data and bearing the parties I am not inclined to sustain the Management's action in terminating the petitioner's services without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the Act because for all intents and purposes it was a case of retrenchment as amplified by the Hon' Judges in the matter of Mohan Lal Vs. Bharat Electronics 1981(3) Supreme Court Cases 225.

6. On behalf of the management it was strenuously argued that in view of the petitioner's unbecoming behaviour towards his co-workers an alarming situation had developed at the project which could disrupt the congenial environment and industrial peace and could not be avoided except on terminating with his services in a summary manner. It was explained that it was precisely for this particular reason that they had to dispense with the formality of a regular inquiry in his misconduct.

7. I am not impressed with the logic of the submission because of the unambiguous mandate of the statute. Of course in the given situation the management might have its own limitations in going through the drill of a regular disciplinary inquiry but all the same they had no justification in denying him the terminal benefits envisaged by Section 25-F of the Act. The termination has, therefore to be struck down.

8. Under the normal circumstances quashing of the impugned order should have led to the petitioner's reinstatement with all the attendant benefits of service but for the maintenance of a congenial and peaceful atmosphere at the Project which is still at the stage of infancy, I direct that instead of being reinstated or re-employed the petitioner be paid a consolidated amount of Rs. 25,000 (Twenty five

Thousand) in full and final settlement of his entire claim. The payment shall be made to him in lump sum before the close of the current financial year failing which the management would further be liable to pay him interest @10 per cent per annum from the date of reference i.e. 17-7-1984.

Chandigarh,
Dated : 10-12-1985. |

I. P. VASISHTHI, Presiding Officer
[No. L-92012(5)/84-D.U(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 1985

का. आ. 133.—उत्प्रवास प्रधिनियम, 1983 (1983 का 31) की घाय 5 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवासी मंडली कायलिय, कोचीन में महायक थी के. एन. एस. नायर को 2 से 6 जनवरी, 1986 तक उत्प्रवासी संरक्षी, कोचीन के भारि कार्य करने के लिए प्राप्तिकृत करती है।

[म. जैड-11025/29/85-एमीग्रेण्ट-II]
अमित दाम गुप्ता, प्रबर मन्त्रिव

New Delhi, the 30th December, 1985

S.O. 133.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorise Sh. K.N.S. Nair, Assistant in the office of the Protector of Emigrants, Cochin to perform all functions of Protector of Emigrants, Cochin with effect from 2nd to 6th January, 1986.

[No. Z-11025/29/85-Emig.II]
AMIT DASGUPTA, Under Secy.